

संक्षिप्त समाचार

इंश्योरेंस पॉलिसी पर एक करोड़ दिलाने का झांसा देकर जाल में फंसाया, पैसे लेकर संपर्क तोड़

अनप्लग इंडिया

नोएडा। नोएडा में साइबर ठाणों ने 81 साल के डॉक्टर से इंश्योरेंस पॉलिसी पर एक करोड़ रुपये लौटाने का झांसा देकर 20 लाख 1 हजार 712 रुपये ठा लिया। ठाणों ने डॉक्टर को उनकी पुरानी पॉलिसी की जानकारी देकर भरोसे में लिया। इसके बाद आठ दिन में 7 बार में रकम ट्रांसफर करा ली। पैसे मिलने के बाद ठाणों ने संपर्क तोड़ लिया। मामले में साइबर थाना पुलिस ने रविवार को केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सेक्टर-27 निवासी डॉक्टर रतिश चंद्र ने पुलिस को बताया कि ठाणों ने पहले उनके वॉट्सएप नंबर पर मैसेज किया। बातचीत के दौरान उन्हें उनकी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी कुछ जानकारी भी भेजी। इसके बाद पॉलिसी पर एक करोड़ रुपये मिलने का ऑफर दिया।

फॉर्म भरवाकर शुरू की ठाणी

डॉक्टर के मुताबिक, ठाणों ने उन्हें कुछ प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा और एक फॉर्म भी भरवाया। इसके बाद पॉलिसी का पैसा दिलाने के नाम पर रकम जमा कराने लगे। शुरुआत में उनसे एक लाख रुपये लिए गए। फिर अलग-अलग प्रक्रिया का हवाला देकर लगातार पैसे ट्रांसफर कराए गए। डॉक्टर ने इस बारे में परिवार के किसी सदस्य को जानकारी नहीं दी और ठाणों की बातों में आकर रकम भेजते रहे।

आठ दिन में 7 बार ट्रांसफर किए रुपये—डॉक्टर ने आठ दिन के अंदर 7 बार में कुल 20 लाख 1 हजार 712 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी उन्हें एक करोड़ रुपये नहीं मिले। जब उन्होंने ठाणों से अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए, तो आरोपियों ने संपर्क तोड़ लिया। इसके बाद डॉक्टर ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर उन बैंक खातों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है, जिनमें रकम ट्रांसफर की गई थी।

नोएडा-ग्रैनो में ऑपरेशन कवच; प्राइवेट बसों की होगी निगरानी, 47 जब्त, 76 के चालान



अनप्लग इंडिया

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के परिवहन विभाग ने दिल्ली से नोएडा होकर जाने वाली एक हजार से अधिक निजी बसों का डाटा तैयार किया है। इसमें सुरक्षा मानकों में कमीयों वाली बसों को एक अलग श्रेणी में रखा गया है ताकि उन पर विशेष रूप से नजर रखी जा सके। अब ऑपरेटर की हर एक बस की विशेष निगरानी की जाएगी। विभाग ने यह कड़ा कदम हाल ही में बसों में गैंगरेज और आग लगने की घटना के बाद लिया है।

इमरजेंसी गेट की कमी

परिवहन विभाग के अनुसार, जिन बसों में फिटनेस, परमिट या सुरक्षा उपकरणों जैसे अनिवशमान यंत्र या इमरजेंसी गेट की कमी मिली है, उन्हें अलग हाई-अलर्ट पर डाला गया है। इन निजी बसों की हर बार सड़क पर उतरने या नियमित अंतराल पर विशेष निगरानी की जाएगी। यदि किसी ऑपरेटर की एक बस में गड़बड़ मिलती है, तो उसके बेड़े की अन्य सभी बसों की भी कड़ई से जांच होगी।

ऑपरेशन कवच के तहत कार्रवाई—एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पंडे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में अनाधिकृत और नियम-विरुद्ध संचालित होने वाली बसों के खिलाफ ऑपरेशन कवच के तहत कार्रवाई की जा रही है।

47 बसें जब्त, 76 के चालान—9 से 11 अक्टूबर तक चले जांच अभियान में 47 बसें जब्त की गईं और 76 बसों के चालान किए गए। इससे पहले चलाए गए जांच अभियान में 87 बसों पर कार्रवाई की गई थी। इसमें में से 80 बसों को बंद किया गया था। तकनीकी निरीक्षण में फेल होने पर बसों का फिटनेस और पंजीकरण निलंबित करने की प्रक्रिया की जा रही है।

आगरा से लेकर नागालैंड तक संचालित हो रही—दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के कई प्रमुख शहरों के लिए निजी बसें संचालित होती हैं। इसमें आगरा से लेकर नागालैंड तक की बसें शामिल हैं। लंबी दूरी के लिए रोडवेज बसों की सुविधा नहीं है। ऐसे में खतरनाक संचालन के बावजूद यात्री इनमें सफर करने को मजबूर हैं। निजी बसों में स्लीपर सीटों की सुविधा दी जाती है, जबकि रोडवेज बसों में स्लीपर बसें नहीं हैं।

प्रतिबंध के बाद भी निजी बसों का रुकना जारी

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना की संभावना के चलते सवारी बैठाने और उतारने पर प्रतिबंध है। जिला प्रशासन की ओर से यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद भी बसें एक्सप्रेसवे पर रोककर सवारियों को बैठाने और उतारने का सिलसिला जारी है।

ट्रैफिक एसआई का वश्मा-मोबाइल तोड़ा, मारपीट तक की; चार चालकों के खिलाफ केस दर्ज



अनप्लग इंडिया

गाजियाबाद। वेब सिटी क्षेत्रांतर्गत एनएच नौ डासना आईएमएस अंडरपास के पास सोमवार सुबह चैकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक ऑटो सीज किए जाने पर आरोपियों ने जमकर हंगामा किया, ऑटो सीज करने से गुस्साए चालकों और उनके साथियों ने ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज, मारपीट की तथा सरकारी कार्य में बाधा डाली। यह घटना 12 अक्टूबर सुबह की है, जब ट्रैफिक पुलिसकर्मों डासना एनएच नौ आईएमएस अंडरपास के पास ड्यूटी पर तैनात थे। ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर विकास कुमार अपनी टीम हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार और कांस्टेबल मनीष कुमार के साथ दिल्ली जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दृष्टिगत यातायात डायवर्जन और चैकिंग ड्यूटी पर थे। इस दौरान डासना की तरफ से गाजियाबाद जाते हुए लापरवाही से आ रहे एक ऑटो को रोक़ा गया, ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां बैठी हुई थीं और आटो के आगे नंबर प्लेट नहीं थी, और जांच करने पर उसका बीमा, प्रदूषण व फिटनेस समाप्त पाया गया। ऑटो चालक जबैर निवासी डासना इडाईविंग लाइसेंस भी नहीं दिखा सका, जिसके बाद ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर ने एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत ऑटो को सीज कर पुलिस लाइन भेज दिया। ऑटो सीज होने से नाराज होकर आरोपी आटो चालक जबैर, बंटी, जोगेन्द्र, तरुण और अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे, विरोध करने पर ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर विकास कुमार का चश्मा खींचकर तोड़ दिया और मोबाइल फोन सड़क पर फेंककर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रमोद कुमार के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और चैकिंग न करने की धमकी दी। इस दौरान वहां यातायात बाधित हो गया जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गये। पीड़ित ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर विकास कुमार ने वेब सिटी थाने में आरोपी आटो चालक जुबैर निवासी डासना तथा बन्टी, जोगेन्द्र व तरुण और अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

नोएडा/गाजियाबाद

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में उद्योगों को बड़ी राहत, बड़े भूखंडों की सब-लीज का रास्ता साफ

अनप्लग इंडिया। डेस्क

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूखंड के कुछ हिस्से सहयोगी कंपनियों को सब-लीज पर देने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस निर्णय से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीड) क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार तथा छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार के इस कदम से बड़ी कंपनियों के आसपास उनकी जरूरत के अनुरूप छोटे उद्योग विकसित हो सकेगें। इससे मुख्य इकाइयों को जरूरी उत्पाद और कलपुर्जे समय पर मिल सकेगें। साथ ही उत्पादन प्रक्रिया को अधिक सुचारु बनाने और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।

छोटी इकाइयों के लिए जमीन हासिल करना होगा आसान

प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शासन और औद्योगिक विकास प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों, पूंजी निवेश तथा रोजगार सृजन जैसे मानकों के आधार पर भूखंड आवंटित

पीलीभीत में रामलीला चंदे के विवाद में तीन लोगों की हत्या, दो कारोबारी भाइयों की भी मौत

अनप्लग इंडिया

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के अमरिया कस्बे में रामलीला कमेटी के चंदे के हिसाब को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सोमवार रात दो गुटों के बीच मारपीट और अंधाधुंध फायरिंग में दो सगे कारोबारी भाइयों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत आठ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे अमरिया थाना क्षेत्र में हुई। विवाद की पृष्ठभूमि रामलीला कमेटी के चंदे के हिसाब-किताब को लेकर बताई जा रही है। आरोप है कि कहासुनी के बाद एक पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला किया और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों के साथ सड़क से गुजर रहा एक राहगीर भी गोली लगने से घायल हो गया।

कारोबारी भाइयों और राहगीर की मौत

इस घटना में जान गंवाने वालों की पहचान मोहित गुप्ता (38), अंकित गुप्ता (30) और कुणाल श्रीवास्तव (18) के रूप में हुई है। मोहित और अंकित कारोबारी भाई थे, जबकि कुणाल कस्बे में एक बुक डिपें में काम करता था। बताया गया है कि वह घटनास्थल के पास से गुजर रहा था, तभी गोली लगने से घायल हो गया। गोलीबारी में मोहित के रिश्तेदार रोज गुप्ता (20) भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अंकित और कुणाल की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में बरेली रेफर किए गए मोहित ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घायल रोज गुप्ता का बरेली में इलाज चल रहा है। दोनों कारोबारी भाइयों की मौत से परिवार में मातम

प्रतापगढ़ में छात्रा से अभद्रता के आरोप में दो युवक गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

अनप्लग इंडिया

प्रतापगढ़। शहर के भंगवा चुंगी चौराहे पर

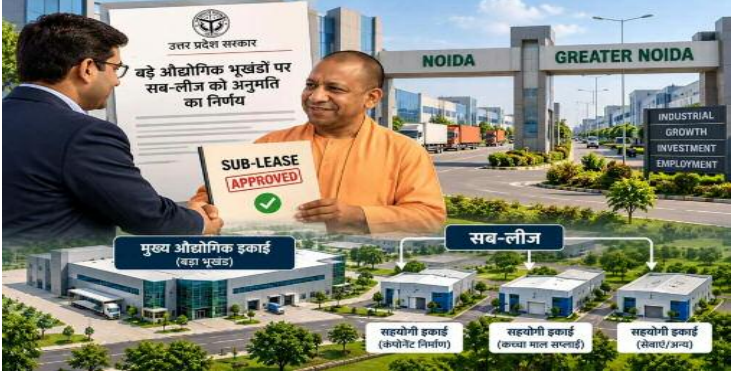
पुलिस चौकी के नजदीक एक छात्रा के साथ कथित छेड़खानी और अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक सवार दो युवकों ने छात्रा का रास्ता रोककर उससे मोबाइल नंबर मांगा और परेशान किया। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए पास स्थित पुलिस चौकी पहुंचकर घटना की जानकारी दी। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

छात्रा को परेशान कर रहे थे बाइक सवार युवक

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम छात्रा भंगवा चुंगी चौराहे पर मौजूद थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक कथित तौर पर उसके आसपास चक्कर लगाने लगे। आरोप है कि दोनों ने छात्रा से मोबाइल नंबर मांगा और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। छात्रा ने स्थिति को भांपते हुए पुलिस चौकी की ओर रुख किया। उसे चौकी की तरफ जाते देखकर दोनों युवक मौके से चले गए। इसके बाद छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

CCTV फुटेज के आधार पर हुई पहचान

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। शिकायत और उपलब्ध फुटेज के आधार



करते हैं। दूसरी ओर, छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूखंड आवंटन में नीलामी की व्यवस्था होने के कारण कई बार जमीन हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

इसका असर उन छोटी कंपनियों पर भी पड़ता है, जो बड़े उद्योगों को कच्चा माल, कलपुर्जे या अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। अब सब-लीज की अनुमति मिलने से बड़ी इकाइयों को आवंटित भूखंड के निर्धारित हिस्से में उनकी सहयोगी कंपनियों की स्थापना का रास्ता खुल सकेगा।

चिप निर्माण से जुड़ी परियोजना को

अनुमति मांगी थी। प्रदेश सरकार के नए निर्णय से ऐसी परियोजनाओं में मुख्य इकाई के साथ संबंधित सहयोगी कंपनियों को भी आसपास स्थापित करने में मदद मिल सकती है। इससे औद्योगिक उत्पादन के लिए जरूरी संसाधनों और उत्पादों की आपूर्ति अधिक सुविधाजनक हो सकती है।

उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मिलेगी मदद

बड़ी औद्योगिक इकाइयों के आसपास छोटी सहयोगी कंपनियां विकसित होने से उत्पादन के लिए जरूरी सामग्री की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। इससे कंपनियों को आपूर्ति के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों में समन्वय बढ़ सकता है।

इसके अलावा, छोटी कंपनियों को बड़े

उद्योगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। इससे औद्योगिक निवेश, रोजगार और स्थानीय स्तर पर कारोबार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

शासनादेश के बाद प्राधिकरण करेगा कार्रवाई

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के साथ सहयोगी इकाइयों को विकसित करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।

खबर के अनुसार, एचसीएल और फॉक्सकॉन की संयुक्त कंपनी इंडिया निप प्राइवेट लिमिटेड ने सेक्टर-28 में आवंटित 48 एकड़ भूखंड में से 24 एकड़ क्षेत्र में एसडीजेड विकसित करने तथा सहयोगी इकाइयों के लिए भूखंड सब-लीज पर देने की

मिलेगी मदद

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राइवेट लिमिटेड ने सेक्टर-28 में आवंटित 48 एकड़ भूखंड में से 24 एकड़ क्षेत्र में एसडीजेड विकसित करने तथा सहयोगी इकाइयों के लिए भूखंड सब-लीज पर देने की

दिसंबर के चौथे सप्ताह में हो सकती है परीक्षा, 3548 पदों पर होगी नियुक्ति

अनप्लग इंडिया

प्रयागराज। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी की स्नातक स्तरीय भर्ती-2026 की प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षाका संभावित कार्यक्रम जारी किया है। उपलब्ध अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा दिसंबर 2026 के चौथे सप्ताह में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

यह भर्ती अधिसूचना संख्या CEN 06/2026 के तहत की जा रही है। हालांकि, परीक्षा की सटीक तारीखों की घोषणा अभी अलग से की जानी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सूचना पर नजर रखें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी तथा यात्रा की योजना बनाएं।

देशभर में भरे जाएंगे 3,548 पद

इस भर्ती अभियान के माध्यम से भारतीय रेलवे में कुल 3,548 रिक्त पदों को भरने की योजना है। इनमें रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज के अंतर्गत 265 पद शामिल बताए गए हैं।

उपलब्ध विवरण के अनुसार, प्रयागराज क्षेत्र में पदों का ब्योरा इस प्रकार है:

गुड्स ट्रेन मैनेजर: 196 पद

चौफ कर्मशियल कम टिकट सुपरवाइजर: 42 पद
सीनियर क्लर्क कम टाईपिस्ट: 27 पद
ये तीनों पद मिलाकर 265 होते हैं। अन्य आरआरबी क्षेत्रों के पदों का विवरण संबंधित आधिकारिक अधिसूचना में देखा जा सकता है।

अलग-अलग पदों पर होंगी ये जिम्मेदारियां

गुड्स ट्रेन मैनेजर: इस पद पर चयनित कर्मचारियों

प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह के अनुसार, बड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ छोटी सहयोगी इकाइयों का इकोसिस्टम विकसित होने से उद्योगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि शासनादेश मिलने के बाद प्राधिकरण उसके अनुरूप कार्रवाई करेगा। इसलिए सब-लीज की अनुमति से जुड़े विस्तृत नियम, शर्तें और प्रक्रिया शासनादेश मिलने के बाद स्पष्ट होंगी।

पतंजलि समूह को पहले भी मिल चुकी है अनुमति

प्रदेश सरकार इससे पहले पतंजलि समूह को भी निर्धारित शर्तों के साथ भूखंड का कुछ हिस्सा सब-लीज पर देने की अनुमति दे चुकी है। खबर के मुताबिक, यीडा के सेक्टर-24ए में समूह को आवंटित 430 एकड़ जमीन में से 20 प्रतिशत हिस्से की सब-लीज की अनुमति दी गई थी।

इसमें शर्त रखी गई थी कि भूखंड की सब-लीज खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों से संबंधित इकाइयों की ही की जा सकेगी। इसके अलावा, जमीन की बिक्री यीडा की प्रचलित दरों के अनुरूप करने की अनुमति दी गई थी।

की जिम्मेदारी मालगाड़ियों के सुरक्षित और सुचारु संचालन से जुड़े कार्यों की होगी।

चौफ कर्मशियल कम टिकट सुपरवाइजर: इस पद पर रेलवे के वाणिज्यिक कामकाज, टिकटिंग और संबंधित यात्री सेवाओं की निगरानी जैसी जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं।

सीनियर क्लर्क कम टाईपिस्ट: इस पद पर कार्यालयी दस्तावेजों, रिकॉर्ड, पत्राचार और अन्य प्रशासनिक कार्यों का दायित्व संभालना होगा।

पदों की विस्तृत जिम्मेदारियों और सेवा शर्तों के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक भर्ती अधिसूचना पढ़नी चाहिए।

परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी क्या करें?

CBT-1 की संभावित समय-सीमा सामने आने के बाद अभ्यर्थियों के लिए अपनी तैयारी को व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें। परीक्षा की निश्चित तारीख घोषित होने से पहले यात्रा टिकट या अन्य व्यवस्थाएं करने में सावधानी बरतें। किसी भी बदलाव या नई सूचना के लिए आधिकारिक नोटिस को ही प्राथमिकता दें।

नौकरी के नाम पर ठगी से रहें सावधान

रेलवे भर्ती के नाम पर नौकरी दिलाने का दावा करने वाले दलालों और फर्जी एजेंटों से सतर्क रहें। किसी व्यक्ति के कहने पर पैसे देकर नौकरी पाने का भरोसा न करें। भर्ती से संबंधित आवेदन, परीक्षा और चयन की जानकारी केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों और अधिसूचनाओं से प्राप्त करें।

60 मीटर रोड से रबूपुरा जाने वाले रास्ते पर पुल चौड़ा, सड़क निर्माण पूरा



अनप्लग इंडिया

यमुना सिटी। 60 मीटर रोड से रबूपुरा जाने वाले रास्ते पर स्थित पुल का चौड़ीकरण और सड़क निर्माण कार्य मंगलवार को पूरा हो गया। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है। पहले पुल संकरा होने और तोड़ा मोड़ होने के कारण यहां हदसों का खतरा बना रहता था। बड़े वाहनों के गुजरने पर जाम भी लग जाता था। पिछले कई महीनों से पुल का चौड़ीकरण और सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था। पुल पर रोड़ी-बजरी बिखरी रहती थी और सड़क ऊबड़-खाबड़ थी। इससे राहगीरों को परेशानी होती थी। सबसे अधिक दिक्कत दोपहिया वाहन चालकों को होती थी, जिन्हें असमतल रास्ते से संभलकर गुजरना पड़ता था। पुल के पास रास्ता संकरा होने के साथ मोड़ करीब 90 डिग्री का था। ऐसे में तेज गति से आने वाले वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते थे, जिससे हदसों का खतरा बढ़ जाता था। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण बड़े वाहनों के निकलने पर अन्य वाहनों को रुकना पड़ता था और जाम लग जाता था। अब निर्माण कार्य पूरा होने से आवागमन सुगम होने और वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

जैतर एयरपोर्ट से जनवरी शुरू हो सकती हैं इंटरनेशनल उड़ानें, अब कितना बचा काम



इस तरह विकसित होंगे रनवे

- 1334 हेक्टेयर में पहला और दूसरा रनवे
- 1365 हेक्टेयर में तीसरा रनवे
- 1318 हेक्टेयर में चौथा रनवे
- 735 हेक्टेयर में पांचवां रनवे

जारी है। हालांकि, अनुमान के मुकाबले एयरपोर्ट से 8 से 10 गुना तक कम यात्री सफर कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल उड़ानों के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।

इंटरनेशनल टर्मिनल पर अब क्या काम बाकी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नायल) के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि इंटरनेशनल टर्मिनल का निर्माण काम पूरा हो चुका है। लाइटिंग, सजावट समेत अन्य प्रकार के कार्य चल रहे हैं। उनका कहना है कि ये सभी कार्य इसी माह में पूरे हो जाएंगे। नवंबर में बकास की टीम भी एयरपोर्ट पर सुरक्षा पहलुओं की जांच शुरू कर देगी। दिसंबर में सभी प्रकार की मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि जनवरी तक इंटरनेशनल उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अभी अलग-अलग शहरों के लिए सेवा चालू है।

इन सुरक्षा मानकों की जांच होगी

अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए यात्री, सामान, एयरलाइन, ग्राउंड हैंडलिंग और एयरपोर्ट के अलग-अलग सुरक्षा क्षेत्र आपस में किस तरह जुड़े हैं, इसकी जांच की जाएगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो

(बकास) इसकी पड़ताल करेगा कि अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल और उससे जुड़ी नई सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। बकास की अंतिम मंजूरी के बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को हरी झंडी दिखाई जा सकेगी।

चार चरणों में पूरा होगा

एयरपोर्ट चार चरणों में बनेगा। 1334 हेक्टेयर में प्रथम फेज पूरा हो गया है। फेज-2 में दूसरा 4500 मीटर का दूसरा रनवे बनाया जाएगा। 2031 तक एयरपोर्ट पर तीन करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे, जबकि दोनों रनवे की क्षमता प्रतिवर्ष सात करोड़ यात्री की होगी। दूसरे चरण की 1365 हेक्टेयर भूमि में एमआरओ हब और सड़क अन्य रनवे समेत एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े काम होंगे।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर को कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल ने जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा-जेवर' रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।



अपनी बात
संपादकीय

चुनावी लोकतंत्र बहाल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्णायक कदम उठाने होंगे

सकार का खुद को संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था के साथ इस तरह जोड़कर देखना बेहद चिंताजनक है। चुनाव आयोग न तो कांकेरपालिका का कोई हिस्सा है और न ही सहायारी पाव के प्रति जवाबदेह कोई प्रशासनिक विभाग। इसकी स्वतंत्रता एक जरूरी सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करने वाले लोग उन हालात में हेरफेर न कर सकें जिनके तहत वह सत्ता दोबारा हासिल की जाती है। भारत का चुनावी लोकतंत्र एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है जहाँ व्यक्तिगत दखल सिर्फ प्रक्रिया की जांच और चिंता जताने तक सीमित नहीं रह सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बढ़ता विवाद, मंचादता सूचियों के विशेष ज्ञान पुनरीक्षण (एसआरओ) के तहत बड़ौदा संख्या में मंचादताओं के नाम हटाना, और जन-विरोध प्रदर्शनों पर सकार



कर दिया गया हो। यह टक्कर चुनावी प्रशासन के पारंपरिक दायरे से काफी आगे निकल चुका है। विश्वीय दल, नागरिक समाज संगठन और दायरे आंदोलन न सिर्फ चुनाव आयोग के अलग-अलग फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि खुद इस संस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। 10 अक्टूबर के प्रदर्शनों से पहले नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना, सर्वजनिक परिवहन पर रोक लगाना और हजारों सुरक्षाकर्मियों की तैनाती न ही धरणा को और मजबूत किया है। एक नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग की आलोचना को अपनी सत्ता के लिए चुनौती मानी है। सरकार का खुद को संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था के साथ इस तरह जोड़कर देखना बेहद चिंताजनक है। चुनाव आयोग न तो कार्यपालिका का कोई हिस्सा है और न ही सत्ताधारी पार्टी के प्रति जवाबदेह कोई प्रशासनिक विभाग। इसकी स्वतंत्रता एक जरूरी सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करने वाले लोग उन हालात में हेरफेर न कर सकें जिनके तहत वह सत्ता दोबारा हासिल की जाती है। जब सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायतों को दूर करने के बजाय उन्हें सर्वजनिक जवाबदेही से बचाने के लिए ज़्यादा तुरंत दिखती है, तो संस्थागत अंतर खतरनाक रूप से धुंधला हो जाता है। ज्ञानेश कुमार को हटाने का संसदीय रास्ता बेहद मुश्किल साबित हुआ है। अनुच्छेद 324(5) मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के जज के गुरजर सुरक्षा देता है। उन्हें हटाने के लिए एक कठिन संसदीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जिससे विश्वश्रु के अलावा बड़े पैमाने पर समर्थन के बिना सफलता लगभग असंभव हो जाती है। यह संवैधानिक सुरक्षा इसलिए बनाई गई थी ताकि चुनावी स्वतंत्रता में कार्यपालिका का मनमाना दखल रोक जा सके। इसका मकसद कभी भी असंवैधानिक कामकाज या प्रशासनिक गड़बड़ को की न्यायिक जांच से हट्ट देना नहीं था। यह फ़र्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करके मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता।

-सौरभ वार्ष्णेय

समझ नहीं आता कि राजनीतिक पार्टी हर बार चुनाव से पहले कमसम से क्यों उलझ कर रह जाती है। जहाँ एक ओर आगामी युवा देश की कमान ऐसे नेता को सौंपना चाहता है जो उनका नेतृत्व कर सकें। वहीं चुनाव पूर्ण रूपानीत को समझने की जगह जनता के सेंटिमेंट को समझ ही नहीं पा रही ? फिर चुनाव बाद पश्चाताप करते दिखाई हैं जैसे ममता देवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह की खींचतान सामने आ रही है, उसने विपक्षी एकता के दावों की वास्तविकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर दोनों दल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मजबूत राजनीतिक चुनौती पेश करने की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी ओर गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या, राजनीतिक प्रभाव और नेतृत्व की प्राथमिकताओं को लेकर असहजता लगातार सामने आ रही है। सवाल केवल सही नहीं है कि सपा किन्तुनी सीटें चाहती है और कांग्रेस किन्तुनी सीटें पर दावा कर रही है। असली सवाल यह है कि क्या दोनों दल उस राजनीतिक समझ और परिपक्वता का परिचय दे पाएंगे, जिसकी अपेक्षा एक प्रभावी गठबंधन से की जाती है?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह कहना कि 'बात सौट की नहीं, जीत की है' इसके मायने अलग हैं वह समझ रहे हैं कि बिना गठबंधन के कुछ नहीं हो सकता? इस पूरे विवाद के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है। उन्होंने गठबंधन की जीत को सीटों की संख्या से ऊपर रखते हुए कहा कि मकसद स्पष्ट हो तो साथ मिलकर मंजिल हासिल की जा सकती है। उनका यह संदेश समाज-कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के बीच एक तरह से राजनीतिक संयम की अपील भी है। लेकिन राजनीति में केवल संदेश काफी नहीं होते। संदेश को जमीन पर उतारने की इच्छाशक्ति और संगठनात्मक क्षमता भी चाहिए। यही वह बिंदु है जहां समाज-कांग्रेस गठबंधन की आखिरी परीक्षा शुरू होती है।

चुनावी गठबंधन कोई ऐसा समझौता नहीं होता जिसमें केवल सीटों का गणित बैठा दिया जाए। गठबंधन का अर्थ है एक-दूसरे के राजनीतिक अजिंकल का सम्मान, साझा रणनीति, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और मतदाताओं को एक स्पष्ट संदेश। यदि शीर्ष नेतृत्व मंच पर एकता की बात करे, लेकिन स्थानीय स्तर पर दोनों दलों के नेता एक-दूसरे के खिलाफ ख्याबाने में, तो जिनके बीच गठबंधन की विश्वसनीयता स्वाभाविक रूप से कमजोर होगी। उत्तर प्रदेश में यह खतरा और भी

बड़ा है, क्योंकि यहां चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच भी लड़ा जाता है। प्रत्येक सीट का अपना अलग-अलग सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक इतिहास होता है। ऐसे में केवल सीटों की संख्या के आधार पर फार्मूला तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। यह देखना होगा कि किस क्षेत्र में किस दल का संगठन



मजबूत है, किस उम्मीदवार की स्वीकार्यता अधिक है और कौन-सा प्रत्याशी विपक्षी मतों को एकजुट कर सकता है।

यही वह व्यावहारिक राजनीति है जिसे समझे बिना गठबंधन का गणित कागज पर तो सुंदर दिखाई दे सकता है, लेकिन चुनावी मैदान में विषय सखा है। भाजपा ने सपा-कांग्रेस के बीच जारी मतभेदों को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का गठबंधन के 'लठमारण' कहना इसी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा के लिए विपक्षी गठबंधन के भीतर का प्रत्येक मतभेद राजनीतिक अवसर है। विपक्ष जितना अधिक एक-दूसरे के खिलाफ बोलगा, भाजपा उतना ही यह संदेश देने को कोशिश करेगी कि उसके सामने खड़ा गठबंधन सत्ता का विकल्प बनने से पहले ही आपसी संघर्ष में उलझ गया है। भाजपा के खिलाफ लड़ाई केवल चुनावी भाषणों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए विपक्षी दलों को अपने भीतर की कमजोरियों पर भी विचार्य हासिल करनी होगी। यह विडंबना है कि जो दल लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय और जनहित के बड़े मुद्दों को लेकर एक मंच पर आने की बात करते हैं, वे स्वयं सीटों के प्रश्न पर सार्वजनिक असहमति का प्रदर्शन करने लगे। जन्ता स्वाभाविक रूप से पुछेगी कि जब सत्ता की साझेदारी अभी हुई भी नहीं है तो सीटों की साझेदारी पर इतना संघर्ष क्यों?

दरअसल, गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ा संकट सीटों की संख्या नहीं, विश्वास का संकट होता है। यदि सपा को कांग्रेस पर और कांग्रेस को सपा पर भरोसा नहीं होगा तो कोई भी सीट समझौता स्थायी नहीं हो सकता। आज एक फार्मुला तय होगा, कल उम्मीदवार चयन पर विवाद होगा और चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की समस्या सामने आएगी। ऐसी स्थिति में गठबंधन का लाभ विशेषी दल को मिल सकता है। इसलिए दोनों दलों को यह स्वीकार करना होगा कि गठबंधन में किसी एक दल की पूर्ण राजनीतिक संतुष्टि संभव नहीं होती। गठबंधन में समझौते करने पड़ते हैं। कुछ सीटें छोड़नी पड़ती हैं ताकि अधिक सीटें जीती जा सकें। राजनीति में कभी-कभी कम सीटों पर लड़ना, अधिक सीटें जीतने में कभी-कभी अधिक सीटें जीतनी ज़रूरी है। इसके विपरीत अधिक सीटों पर लड़ने का अहंकार कई बार जीत की संभावनाओं को ही कमजोर कर देता है।

अखिलेश यादव का 'बात सीट की नहीं, जीत की है' वाला कथन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें गठबंधन की राजनीति का मूल तत्व छिपा हुआ है। यदि सच और कांग्रेस वास्तव में भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपने-अपने राजनीतिक विस्तार की चिंता के साथ-साथ साझा राजनीतिक लक्ष्य पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन कांग्रेस की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपने अंगवस्त्रक और राजनीतिक प्रभाव को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यदि वह लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है तो उसे सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से होगी। दूसरी ओर सपा का तर्क यह हो सकता है कि जमीनी ताकत और चुनौती संभावना के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। दोनों पक्षों की अपनी राजनीतिक मजबूरियाँ हैं। समाधान तभी निकलेगा जब दोनों दल अपनी मांगों को अंतिम तथ्य मानने के बजाय जीत की संभावना को केंद्र में रखेंगे।

यह भी याद रखना होगा कि चुनाव केवल नेताओं का नहीं होता। चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं। यदि सपा का कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी को और कांग्रेस का कार्यकर्ता सपा प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार स्वीकार नहीं करता तो गठबंधन का पूरा गणित बिगड़ सकता है। इसलिए सीट समझौते के साथ साझा चुनाव अभियान, संयुक्त सभाएं, स्पष्ट संदेश और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय भी जरूरी होगा।

आज देश की राजनीति में गठबंधन कोई असामान्य

घटना नहीं है। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न दलों का साथ आना लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन गठबंधन तोभी सफल होते हैं जब उनके पीछे सच्चा न्यूनमत कायंम और पारस्परिक विश्वास हो। केवल किसी एक दल को रोकने के लिए बना गठबंधन लंबे समय तक जनता का विश्वास कायम नहीं रख सकता। मतदाता यह जानना चाहता है कि उसके सामने विकल्प क्या है, उस विकल्प को नीति क्या है और सत्ता मिलने पर वह क्या करेगा।

उन्हें केवल भाजपा विरोधी मंच नहीं बनना है, बल्कि जनता के सामने शासन और विकास की विश्वसनीय विकल्प भी प्रस्तुत करना है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय, युवाओं के अवसर, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर स्पष्ट साझा दृष्टिकोण सामने रखना होगा। केवल सौतों का समझौता चुनाव नहीं जिताना; जनता के स्वालों का विश्वसनीय जवाब चुनाव जिताना है।

इस समय सपा और कांग्रेस को यह तय करना होगा कि उनके लिए प्राथमिकता राजनीतिक प्रतिष्ठा है या चुनावी सफलता। यदि दोनों दल अपने-अपने प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हैं तो राजनीतिक अहंकार को सर्वोपरि रखेंगे तो गठबंधन संभव होगा। यदि वे जीत को प्राथमिकता देंगे तो सीटों का विवाद बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत कुछ देख चुकी है। वह नेताओं के बयान भी सुनती है और उनके व्यवहार का आकलन भी करती है। वह यह भी समझती है कि कौन-सा विवाद वास्तविक है और कौन-सा केवल चुनावी दबाव बनाने की रणनीति। इसलिए अब समय सार्वजनिक बयानबाजी बढ़ाने का नहीं, बल्कि कड़े कर्मों में गंभीर बातचीत करने का है। सीटों का फैसला आंकड़ों, ज़मीनी ताकत और जीत की संभावना के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव या अहंकार के आधार पर।

सपा-कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन कितनी सीटें लेगा। सवाल यह है कि दोनों दल मिलकर अंतर की सीटें जीत सकते हैं। यदि दोनों दल मिलकर अंतर को समझ लेते हैं तो गठबंधन एक मजबूत चुनावी ताकत बन सकता है। लेकिन यदि सीटों की खींची-ताना राजनीतिक स्वर्चस्व की लड़ाई बन गई तो विपक्षी एकता का सपना चुनावी मैदान में ही बिखर सकता है। यह समझना होगा कि बात समसुच सीटों की नहीं, जीत की है लेकिन जीत के लिए सबसे पहले गठबंधन के भीतर विश्वास की जरूरत है।

**मुखौटे : झूठी अच्छाई,
सच्ची बुराई**



-हेमेन्द्र क्षीरसाग

चेंद्रे तो सबके पास बहुत हैं, बस एक रावण ही था जिसने छिपाए नहीं। रामायण का रावण युग-युग से अमर्य, अकाल और बुराई के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा। विजयदाशमी की हर शाम जलते हुए रावण के पिंजरे के साथ समाज जब संदेश देता है कि अंततः सत्य की विजय होती है और असत्य का विनाश। लेकिन जब हम रावण के दस सिरों के प्रतीकात्मक अर्थ और उस पर की गई हर संस्कृत पक्तियों। 'चेंद्रे तो सबके पास बहुत हैं, बस एक रावण ही था जिसने छिपाए नहीं' पर विचार करते हैं। तो यह आधुनिक सभ्यता के मुह पर एक करारा तमाचा जड़ती है। बेला में इस नवरात्र के दशरथ पर हम दशनाम का दहन कर सचरात्र का विजय पत्र मानने की इतिश्री करेंगे। यह विचार रावण के दुष्कर्मा का महिमापावन नहीं करता, बल्कि आज के समाज में त्याग पांडित्य और छत्राचारण की गरि

शाल्य-धिकृतिस्सा करता है। रावण के पास दसरस लाखों आदमी हैं और उसी तरह सिंघासिंह भी है। यानी इस अलग-अलग मनोवृत्तियाँ आपसी विचार। लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वह अपने कभी अपने किसी रूप को छिपाने की कोशिश नहीं करती। वह जैसा भी था, अहंकारी का स्वभाव, महाज्ञानी या क्रूर खुलेआम था। उसका अर्थात् अर्थात् एक फर्जी आवरण पहनकर समाज को धोखा देने का प्रयास नहीं किया। उसका अभ्युक्ति ही मैं समझे था और उसकी शत्रुता भी खुली। मैंने इससे ठीक विपरीत, आज के आधुनिक इंसान को देखिए। आज व्यक्ति चेहरे पर चेहरा लगाए घूम रहा है। बाहर से बेहतरीन व्यक्ति, आन्तरिक रूप से तो सदाचारी दिखने वाला व्यक्ति भीतर से ईर्ष्या, स्वार्थ और छल-कपट से भरा हो सकता है। आज का समाज बड़े-छोटे संस्कृतिक परिवर्तन है। हम समाज में मित्र हैं और पीछे पीछे शत्रु, सार्वजनिक मंचों पर नैतिकता के उपदेश देते हैं और व्यक्तिगत जीवन में स्वार्थी। आज के युग में मैं सबसे बड़ा खतरा उस बुराई से नहीं है जो खुलकर सामने आती है, क्योंकि खुली बुराई से सावधान रहना आसान होता है। असली खतरा सामने नहीं आता, जो गुप्त अभ्युक्ति से है जो धर्म, अच्छाई और सहानुभूति का नकाब पहनकर आता है। यही उचित वास्तव में हमें अपने भीतर झांकने और आधुनिक चेतन करने का अवसर देती है। यह सालगा उत्पत्ति है कि दस सिंघासिंहावा रावण की स्पष्टतः बेहतर थी या एक सिंघासिंहावा अधुनिक मानव के वे दर्जनों छिपे हुए मुखौटे? यदि हम एक बेहतर और पारदर्शी समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें दोहरे चक्र की इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। झूठी अच्छाई के सौ मुखौटे पहनने से कहेंगे अधिक सम्मानजनक है कि इंसान अपने वास्तविक रूप में निष्कल और पारदर्शी बनकर सच्ची बुराई करें।



महेन्द्र तिवारी
साहित्यकार एवं लेखक
पूर्व वायुसैनिक

लोकतंत्र की जीवंतता केवल इस बात से तय नहीं होती कि संसद के भीतर सत्ता-पक्ष और विपक्ष के बीच किन्तानों सार्थक बहस होती है, बल्कि इसकी असली कसौटी यह है कि संसद के बाहर सुझाव पर आम नागरिक की आवाज को कितनी गंभीरता और सहजता से सुना जाता है। देश की राजधानी नई दिल्ली के हृदयस्थल में स्थित जंतर मंतर पिछले 33 वर्षों से इसी लोकतांत्रिक चेतना, जन आक्रोश और नागरिक उम्मीदों का सबसे बड़ा केन्द्र रहा है। किंतु एक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए जंतर मंतर को अधिकृत प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया है। 28 अप्रैल 2022 को के पुनः स्थायी आदेश में संशोधन करते हुए आम राजधानी में धरना और प्रदर्शन के

लिया तोन नए स्थान निर्धारित किए गए हैं। उत्तरी मध्य दिल्ली का रामलीला मैदान जमिनी दिल्ली का बुराड़ी मैदान और पूर्व दिल्ली के कड़कड़डुमा स्थित व्यावसायिक केंद्र मैदान शामिल हैं। प्रशासन के इस एनर्जियन ने तीन दशकों से चली आ रही प्रतिरोध की एक पूरी परंपरा को विराम दे दिया है और साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों तथा प्रशासनिक व्यवस्था के बीच के द्वंद पर एक नई बखस छोट दी है। जती मंतर का यह परिसर केवल 18वें सदी के खगोलीय यंत्रों का स्मारक माना नहीं था, बल्कि यह आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका था। वर्ष 1993 से लेकर 2026 तक के अपने 33 वर्षों के सफर में इस छोटे से मार्ग ने अनगिनत ऐतिहासिक बदलावों की नींव रखी। चाहे वर्ष 2011 का भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन हो, वर्ष 2012 में स्फूर्ती कांड के बाद उमड़ा युवाओं का स्वतः-पथी जनसेलबाज हो, वर्ष 2015 में पूर्व सीनिकों का वन रैंक वन पेशा आंदोलन हो या फिर वर्ष 2023 में महिला पहचानों का लंबा सघर्ष, जंतर मंतर ने हज़ारों की पीढ़ी को राष्ट्रीय पटल पर रबने का मंच प्रदान किया। देश के सुदूर कोनों से आने वाले किसानों, मजदूरों, छात्रों, शिक्षकों और वंचित वर्गों के लिए एक स्थान एक ऐसी उम्मीद की तरह था, जहाँ खड़े होकर वे सीधे शासक के शीर्ष से सवाल करने का अहसास पाते थे। संसद भवन से मगर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होना

के कारण यहाँ उठने वाली हर आवाज व गूँज नीचे निर्माताओं के कानों तक आसानी से पहुँच जाता थी। इस ऐतिहासिक स्थान से प्रदर्शनों को हटाने के पीछे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के अपने ठोस तर्क हैं। तात्कालिक कारणों पर नजर डालें तो व 2026 के जून और जुलाई माह प्रतियोगी पक्षों की शुभिता और विश्व सुधारों की मांग को लेकर लगभग 36 दिनों तक चला विशाल खूब आंदोलन इस फैसले का मुख्य आधार बना। उस आंदोलन के दौरान जंतर मंतर की सीमा श्रमता के विपरित 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी जुट गए थे। जब इस भां भीड़ ने संसद भवन की ओर कूच करना का प्रयास किया, तो सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई और पुलिस तथा छात्रों के बीच हुई झड़पों में 118 पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों छात्र घायल हुए। इसके अतिरिक्त हाल ही में मराठवाड़ा सूची के विशेष न संसोधन के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और युवा संगठनों द्वारा फिर से जंतर मंतर में बड़े घेराव की तैयारी की जा रही थी। न संसद भवन और कर्तव्य पथ के आसपास अति विशिष्ट व्यक्तियों के निरंतर आवामान और संसद-नशील मालंग्यों व सुरक्षा को देखते हुए पुलिस का मानना कि इतनी कम दूरी पर अनियंत्रित भीड़ व जुटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम है। सुरक्षा के अलावा स्थानीय व्यापारिक और आम नागरिकों की दैनिक परेशानियाँ भी इस बदलाव का एक बड़ा कारण बन हैं। जंतर मंतर राश्वानी के सबसे ब

व्यावसायिक केंद्र कॉन्ट प्लेस और जनपथ के ठीक बगल में स्थित है। जब भी यहाँ कोई बड़ा प्रदर्शन होता था, तो एहद्विगत केंद्रों के तौर पर आसपास की मुख्य सड़कें और रेलवे के भूमिगत स्टेशन बंद कर दिए जाते थे। इससे न केवल घंटों लंबा यातायात जमना लगता था, बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की ओर जाने वाले हज़ारों यात्रियों की गाड़ियाँ छूट जाती हैं। स्थानीय व्यापार मंडलों ने लंबे समय से यह शिकायत की थी कि लगातार होने वाले धरनों और नाकेबंदी के कारण कॉन्ट प्लेस केंद्र के व्यापार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूर्व में यह सुझाव दिया था कि प्रदर्शनों के लिए ऐसी खुली और बड़ी जगह तलाशी जानी चाहिए जहाँ आम जनजीवन प्रभावित न हो तथा प्रदर्शनकारियों के लिए पेयजल, शौचालय और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें। किंतु इस प्रशासनिक सुविधा के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो नागरिक अधिकार समठानों और संविधानविदों की चिंताएं अत्यंत गंभीर और विचारणीय हैं। राजधानी में सत्ता के केंद्र से जन आंदोलनों को दूर धकेलने की यह प्रवृत्ति नई नहीं है। बल्कि पिछले चार दशकों में विरोध का पता तीन बार बदला जा चुका है। वर्ष 1988 तक इंडिया गेट के पास स्थित लोक कला दश के सबसे बड़े प्रदर्शनों का केंद्र हुआ करता था, जहाँ से संसद और राष्ट्रपति भवन सीधे दिखाई देते थे। अक्टूबर 1988 में चौथी मंढेर सिस

टिक्कैत के नेतृत्व में जब 5 लाख किसानों ने एक सप्ताह तक बौट क्लब पर डेरा डाला, तो सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था का हवाला देकर वहां प्रदर्शनों पर स्थायी रूप से रोक लगा दी और वर्षों 1993 में जंतर मंतर को नया नाम विकल्प बनाया गया। वर्ष 2011 में राष्ट्रीय हड़ित अधिकरण ने पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का हवाला देकर जंतर मंतर पर भी आंशिक पाबंदियां लगाईं और अब वर्ष 2026 में इसे पूरी तरह से सूची से हटा दिया गया है। बौट क्लब से जंतर मंतर और अब जंतर मंतर से बुराड़ी मैदान तथा कड़कड़झमा के मैदानों तक का सफर वास्तव में सत्ता के गलियारों से आम जनता की भौतिक और मानवीयवाकिक दूर बढ़ने की कहानी है। लोकतंत्र में किसी भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का मूल उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना और राष्ट्रीय समाचार माध्यमों के जरिए आसानी बात देश के सामने रखना होता है। जंतर मंतर की भौगोलिक स्थिति उसी यह विषय महत्व देती थी कि वहां बैठे सौ लोगों का एक छोटा समूह भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता था। इसके विपरीत, उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी मैदान या पूर्वी दिल्ली का कड़कड़झमा मुख्य प्रशासनिक केंद्र से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बारह इलाकों में प्रदर्शनों को स्थानांतरित करने से प्रशासन को भीड़ प्रबंधन में तैयार आसानी होगी, लेकिन इससे जीला-आंदोलनों की दृश्यता और प्रभावशीलता कम होने का पूरा अंदेश है। जब विरोध

की आवाज सत्ता के केंद्र से बहुत दूर किसी कोने में सिमट जाती है। तो उसकी अनदेखी करना तंत्र के लिए बहुत आसान हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(ख) देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण और निशस्त्र सम्मेलन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2018 के मजबूत किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सघ मामले में स्पष्ट रूप से कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर नागरिकों के विरोध करने के अधिकार को पूरी तरह से निष्प्रभावी या अर्थहीन नहीं बनाया जा सकता। शासन का यह दावित है कि वह सुरक्षा और नानागिक स्वतंत्रता के बीच एक स्वस्थ संतुलन कायम करे। यदि सुरक्षा चुनौतियों और शहरी यातायात के दबाव के कारण जंतर मंतर से प्रदर्शनों को हटाना अपरिहार्य ही था, तो सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि रामलीला मैदान, बुराड़ी कड़क इड्डूमा के नए स्थलों पर आने वाले नागरिकों की आवाज अनसुनी न रहे। लोकतंत्र की गतिमा इसी में है कि प्रदर्शन का मैदान भले ही बदल जाए, लेकिन जनतन्त्र की पीढ़ी को सुनने की सत्ता की संवेदनशीलता कभी कम न हो।

पद से नहीं जनविश्वास से बनता है जननायक



कुंवर शील वर्धन प्रताप नारायण सिंह
एडवोकेट/पत्रकार
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
गोरखपुर प्रेस क्लब

लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति सत्ता के वैभव, पद की प्रतियोग अथवा बहुमत के अहंकार में नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के नैतिक साहस, कर्तव्यनिष्ठा और जनसरोकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता में निहित होती है। लोकतंत्र उन्हीं विषयवस्तुओं के बल पर जीवित और संरक्षित बना रहता है, जो उपेक्षितों की आवाज बनते हैं, जनसमस्याओं को मुखरता से उठाते हैं और विषय परिसंस्थितियों में भी सत्य के पथ में खड़े रहने का साहस रखते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक दल की सीमा में सिमझकर नहीं रह जाते, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करते हैं।

[illegible]

है। जनप्रतिनिधित्व का वास्तविक अर्थ यह है कि सदन की कार्यवाही जनसामान्यता की की अपेक्षाओं से जुड़ी रहे और व्यवस्था को समझ उन प्रश्नों को रखा जाए, जिससे समाज का भविष्य निर्धारित होता है। लोकतंत्र को बोलना और अपनाकर सर्वे सहज नहीं हो पाता है। विशेषकर तब, जब सत्ता के प्रचंड बहुमत को ही जनमत की अंतिम अभिव्यक्ति मान लिया जाए और अश्वमेध की अनुकरण विरोध समझने की प्रवृत्ति विकसित होने लगे। अतः बहुमत का अर्थ अनुरक्तता नहीं अंश असमर्थता का अर्थ अनुसंधानहीनता का होता है। लोकतंत्र की सार्थकता इसी में है कि विचारों के मतभेद के बावजूद सत्ता में परंपरा जीवित रहे तथा जनतंत्र से जुड़े प्रश्नों को निर्भीकता से उठाने वालों का सम्मान विचारों के मतभेद के बावजूद प्रहरी वहीं है जो सत्ता की निकटता से अधिक जनता के विश्वास को महत्व देता है। वह गुमाना आवाजों को अभिव्यक्ति देता है, व्यवस्था को अभिव्यक्तियों पर प्रश्न उठाता है और अपमानात्मकता के निर्द्वंद्व में व्यक्तिगत लाभ और जनता के विश्वास के बीच है। ऐसा व्यक्ति जनतंत्र को विश्वास नहीं उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थक अश्वमेध की छुट्टि में उनकी राजनीतिक पहचान और संघर्षशीलता और जनसरोकार से निम्नित है। हाल के दिनों में राजनीतिक शिष्टाचार

पारम्परिक मर्यादा और जनप्रतिनिधियों के आधार पर एक सम्मान को लेकर उठे वाला प्रश्न चर्चाएँ एक भीषण प्रश्न खड़ा करती हैं। क्या संगठन में किसी पद पर आसीन हो जाये व्यक्ति को दूसरों के संघर्ष, अनुभव और योगदान की उसका प्रयोग का अधिकार दे देना है? क्या सार्वजनिक जीवन में वरिष्ठता जनाधार और लंबे राजनीतिक अनुभव को प्रति सम्मान प्रदर्शित करना नेतृत्व का अनिवार्य जिम्मेदारी नहीं है? किसी भी राजनीतिक संगठन की मजबूती केवल उसका पदाधिकारियों की संख्या अथवा संगठनात्मक संरचना से नहीं, बल्कि उसके सदस्यों के पारस्परिक विश्वास, संवाद और आचरण के गरिमा से निर्धारित होती है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेतृत्व से जुड़े विनोद राय सार्वजनिक भी नहीं अपेक्षा प्रासंगिक है कि राजनीतिक मतभेदों और संगठनात्मक संघर्षों के निर्वहन में किसी एवं विवेक का दायित्वों पर रखा जाए। किसी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता अथवा चुनौती अनुभव पर व्यक्तिगत आधिपत्य करना स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श पर टिप्पणी करना असंगत है। मूल प्रश्न यह है कि सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति अपना व्यवहार से किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति विकास करेगा है। पद प्राप्त करने पर उल्लेखी हो सकती है, किंतु पद की गरिमा के बिना राजना कर्ता अधिक बड़ी जिम्मेदारी दे देना प्रताप सिंह की राजनीतिक यात्रा व किसी वर्तमान पदाधिकारी की संगठनात्मक

स्थिति के सापेक्ष सीमित करके नहीं देखा सकता। दशकों के सार्वजनिक जीवन अर्जित अनुभव, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता से विकसित संबंध और शिक्षक-कर्मचारी के बीच स्थापित पहचान समय, श्रम तन्त्रित संघर्ष का परिणाम होते हैं। किसी राजनीतिक लेखन में नए नेतृत्व का स्वागत होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही नहीं है। राजनीतिविश्यों के योगदान का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अनुभव से सीखना और कनिष्ठों को बढ़ने का अवसर देना ही स्वस्थ राजनीति परंपरा का आधार है। राजनीति में पद स्थान नहीं होते। समय के साथ दायित्व बदलते नेतृत्व बदलता है और परिस्थितियाँ भी। देशा प्रहण करती हैं। स्थायी वही रहता है, अपने आचरण, विचार और जनसेवा माध्यम से समाज के मन में स्थान बना लेता है। अहंकार व्यक्ति की उपलब्धियों को क्षय करता है, जबकि विनम्रता उसकी प्रतिष्ठा व्यापक बनाती है। आसमान की और थूथन की कक्षवत इसी शाश्वत सत्य का स्वरूप करती है कि दूसरों का आनाद करके व्यक्ति अंततः अपनी ही गरिमा को खोकर करता है। पूर्वावलोकन की राजनीतिक चेष्टा सदैव संघर्ष, खोप्राप्तिमान और जनसरोकारों प्रेरित रही है। यह के जागरूक नागरिक और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वे कदम उनकी समस्याओं को सदन में उठाकर बालिक सार्वजनिक जीवन में लोतांतां

मर्यादाओं का भी पालन करें। देवदेव प्रताप सिंह के प्रति उनके समर्थकों का सम्मान इसी जनभावना का हिस्सा है। तथापि, किसी भी जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा का वास्तविक आधार उसका निरंतर जनसेवा के प्रति समर्पण और अपने दायित्वों के प्रति ईमानदारी ही होता है। लोकतंत्र की रक्षा केवल भाषणों, नारों और राजनीतिक मुद्दों से नहीं होती। इसके लिए संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, असहमति के प्रति सहिष्णुता, जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और सार्वजनिक जीवन में शालीनता आवश्यक है। राजनीति में प्रतिस्पर्धा है, किंतु कटुता नहीं; आलोचना हो, किंतु व्यक्तिगत हमला नहीं; मतभेद हैं, किंतु संवाद के द्वार खोलने में नहीं। अंततः यह समझना आवश्यक है कि राजनीति में पद से प्रतिष्ठा मिल सकती है, परंतु जनविश्वास अर्जित करना पड़ता है। जनता के हित में स्थान बनाने वाला जनप्रतिनिधि अपने संबंध, आचरण और सेवाभाव से पहचाना जाता है। देवदेव प्रताप सिंह के राजनीतिक जीवन से जुड़ी यह बहस भी इसी व्यापक संदेश को रेखांकित करती है कि लोकतंत्र की असली शक्ति पद की ऊँचाई में नहीं, जनविश्वास की गहराई में निहित होती है। सार्वजनिक जीवन में सम्मान मांगने से नहीं, अपने आचरण से अर्जित किया जाता है; और जो नेतृत्व इस सत्य को आत्मसात कर लेता है, वही लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ बनाने में सार्थक योगदान दे सकता है।

संक्षिप्त डायरी

किशोरी को सुलभ शौचालय में खींच ले गया

आरोपी, किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी

वाराणसी। चौक थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि बेनियाबाग पार्क के पास स्थित एक सुलभ शौचालय में आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी दुलार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना चौक थाना क्षेत्र के बेनियाबाग पार्क के समीप की है। आरोप है कि यहां स्थित सुलभ शौचालय में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। किशोरी की बात सुनने के बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क कर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुलार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने की कार्रवाई एसपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी के अनुसार, 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। प्रकरण में नामजद आरोपी दुलार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

डायट में कला- संस्कृति महोत्सव का आयोजन, शिक्षकों ने दिखाई प्रतिभा

एजेंसी

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में सोमवार को कला संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें वैसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा डायट के प्रशिक्षुओं ने अपनी कलात्मक और सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्य एवं डायट प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने फीता काटकर किया। इसके बाद मां सरस्वती का पूजन किया गया। संस्थान के प्रशिक्षुओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों एवं निर्णायक मंडल का बुके और अंगवस्त्रम भेंटकर स्वागत किया गया। इसके बाद प्रशिक्षुओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन धर्मेन्द्र शर्मा ने किया। इस दौरान प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कला एवं संस्कृति महोत्सव भी इसी पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ कला और संस्कृति को जोड़ना तथा शिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है।

सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत, मुख्यमंत्री ने दुख जताया

एजेंसी

बदायूं. । उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बिसौली थानाक्षेत्र में सोमवार को एक स्कूल की बस और बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई और एक घायल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर जनपद में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त करते हुए घायल को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों से सवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक, बिसौली पुलिस स्टेशन इलाके के मदनजुड़ी गांव के पास एसडीबी स्कूल बस ने बाइक से जा रहे चार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार हत्था गांव निवासी निखिल उर्फ नितिन (19), रोहन (20) और ऋषभ (18) की मौत हो गई, जबकि शिव कुमार घायल हुए। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त चार युवक एक ही बाइक पर सवार थे और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रख था। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हुए पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पीयू की सांस्कृतिक संंध्या में सुर, ताल और नृत्य ने बांधा समां

विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को मंच देने का संकल्प: कुलपति एजेंसी

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम में रविवार शाम आयोजित सांस्कृतिक संंध्या में विद्यार्थियों ने गायन, वादन और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। नवरात्र के प्रथम दिन आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से हुई, जिससे परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी सुनील कुमार ने कार्यक्रम की जानकारी सोमवार को पत्रकारों से साझा की है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि विश्वविद्यालय में असीम संभावनाएं और कलात्मक प्रतिभा है। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि संगीत, साहित्य, नृत्य और लोक संस्कृति विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारते हैं। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच देने के लिए ऐसे आयोजन निरंतर करता रहेगा। सांस्कृतिक संंध्या का विशेष आकर्षण पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह की प्रस्तुति रही। उन्होंने अपने म्यूजिक एल्बम के चर्चित गीत सुनाकर दर्शकों की वाहवाही बटोरी। टीडी कॉलेज के संगीत शिक्षक डॉ. नरेंद्र पाठक ने भी गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन सलमान शेख और छात्रा ईश्विका सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रो. अविनाश, प्रो. प्रमोद कुमार यादव, प्रो. रजनीश भास्कर, प्रो. मनोज मिश्र, डॉ. अन्नु त्यागी, रजनीश सिंह और डॉ. कृष्णा सिंह सहित शिक्षक, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन

एजेंसी

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में राहुल गांधी एवं कांग्रेस सांसद की ओर से महिलाओं पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। महिला कार्यकताओं ने भाजपा प्रेे अटल भवन कार्यालय से पैदल जुलूस निकाला और अंबेडकर तिराहे पर पहुंचकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया और काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। प्रदर्शन का नेतृत्व उतरीला नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सविता गुप्ता, भाजपा जिला उपअध्यक्ष आद्या सिंह पिंकी और वंदना पासवान ने किया। उतरीला नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सविता गुप्ता ने कहा, महिलाओं का सम्मान किसी भी सभ्य समाज की पहचान है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को अपनी भाषा और आचरण की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे पर भाजपा महिला मोर्चा चुप नहीं बैठेगा। हम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। भाजपा जिला उपअध्यक्ष आद्या सिंह पिंकी ने कहा, महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दे रही हैं। ऐसे में महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं का सम्मान केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नेताओं के व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए।

गंगा का पानी उतरने के बाद भी

घाटों पर सिल्ट सफाई की चुनौती,

एजेंसी

वाराणसी। गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी काशी के घाटों की रौनक पूरी तरह नहीं लौट सकी है। बाढ़ का पानी उतरने के साथ घाटों की सीढ़ियों, संपर्क मार्गों और किनारे के हिस्सों पर जमा सिल्ट, कीचड़ और गंदगी अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। कई प्रमुख घाटों पर फिसलन के कारण श्रद्धालुओं, पर्यटकों और पुरोहितों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, नमो घाट पर प्रस्तावित एयर शो, छठ पूजा और देव दीपावली जैसे बड़े आयोजनों को देखते हुए नगर निगम ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। घाटों की सफाई के लिए 15 से अधिक पंपों के साथ सफाईकर्मियों और मजदूरों को



लगाया गया है। गंगा का जलस्तर चेतवनी बिंदु से काफी नीचे आने के बावजूद घाटों पर जमा गाद की समस्या बनी हुई है। पानी उतरने के बाद सीढ़ियों और रास्तों पर रह गई सिल्ट को हटाना नगर निगम के लिए चुनौती बन गया है। घाटों की सुंदरता प्रभावित होने के साथ ही श्रद्धालुओं की आवाजाही भी बाधित

खेकड़ा अग्निकांड में एक और मौत, मृतकों की संख्या चार हुई

एजेंसी

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में आठ अक्टूबर को हुए भीषण अग्निकांड में गंभीर रूप से झुलसे व्यापारी विनय जैन के बेटे अंकुर जैन की सोमवार तड़के दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या चार हो गई है। मृतकों में एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल हैं। परिजनों के अनुसार, अंकुर जैन की हालत पहले स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन सोमवार सुबह करीब तीन बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे में उनकी पत्नी स्वाति जैन (37) और सात वर्षीय बेटी अनन्या जैन की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, आग में फंसे लोगों को बचाने के दौरान गंभीर रूप से झुलसे घास मंडी निवासी कपिल कुमार की शुरुकार को सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। आग लगने की घटना के बाद अंकुर जैन, पड़ोसी युवक जाहिद और कपिल कुमार को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जाहिद का अभी उपचार चल रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका खेकड़ा कस्बे के पास बाजार में पुलिस चौकी के पास स्थित विनय जैन के मकान और परचून की दुकान में आठ अक्टूबर की सुबह करीब आठ बजे आग लग गई थी। शुरूआती जानकारी के मुताबिक, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी। इस दौरान सिलेंडर फटने की भी बात सामने आई थी। आग तेजी से फैलने के कारण मकान की उपरी मंजिल पर मौजूद लोग अंदर फंस गए थे। अंकुर की मौत पर बाजार बंद अंकुर जैन की मौत की खबर मिलते ही खेकड़ा कस्बे में शोक छा गया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से जैन समाज और व्यापारी वर्ग में शोक की लहर है।

बाढ़ प्रभावित 422 किसानों को मिले चेक, आपदा पीड़ितों को 78.52 लाख की मदद

एजेंसी

कानपुर। बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों व परिवारों की राहत देने के लिए जिले में 78 लाख 52 हजार 48 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। सोमवार को सरसेया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बाढ़ से प्रभावित 422 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के चेक वितरित किए। वहीं, बारिश के कारण हुई जनहानि और मकानों को नुकसान पहुंचने के मामलों में भी प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाना जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राहत वितरण में देरी न हो और किसी भी पात्र प्रभावित को सरकारी सहायता से वंचित न रखा जाए। कार्यक्रम में

गोरखपुर में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। गंगा नदी में आई बाढ़ से सदर तहसील के हिन्दूपुर, चिरान, प्रतापपुर हरि, पुष्पगंज और कंठी ख्यौरा गांवों में खेती प्रभावित हुई थी। इन पांच गांवों के 387 किसानों को कुल सात लाख 73 हजार 375 रुपये का कृषि निवेश अनुदान दिया गया। यहां 22.4761 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा था। उमर, नर्वल तहसील के देवसढ़ गांव के मजरा खेड़ा डोमनपुर में पांडु नदी की बाढ़ से प्रभावित 35 किसानों को 98 हजार 173 रुपये की सहायता मिली। इस क्षेत्र में 5.0607 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई थी। दोनों तहसीलों के 422 किसानों को कुल आठ लाख 71 हजार 548 रुपये दिए गए। प्रभावित कृषि क्षेत्र का कुल रकबा 27.5368 हेक्टेयर है। सहायता पाने वाले किसानों में सबूदयाल, जगदीश, तुलसीराम, मुन्ना,

रोकेश, कालीचरण, रमेश, जगनाथ, सुरेश और सैम शामिल रहे। जिले में एक अप्रैल से अब तक अतिवृष्टि के कारण हुई 15 जनहानियों के मामलों में प्रभावित परिवारों को 60 लाख रुपये की सहायता दी गई है। बारिश से मकानों को हुए नुकसान के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों में अनुदान स्वीकृत किया गया। इसके अलावा पूरी तरह क्षतिग्रस्त एक कच्चे मकान के लिए एक लाख 20 हजार रुपये की मदद दी गई। जनहानि और आवासीय क्षति के मद में कुल 69 लाख 80 हजार 500 रुपये वितरित किए गए। किसानों को दिए गए कृषि निवेश अनुदान को शामिल करने पर कुल सहायता राशि 78 लाख 52 हजार 48 रुपये हो गई है। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. विवेक चतुर्वेदी, तहसीलदार सरदर विनय द्विवेदी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

नौकरपेशा लोग, विद्यार्थी, दुकानदार और अन्य नागरिक इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में जाम लगने पर लोगों की दिनचर्या प्रभावित होती है। समय पर स्कूल, कार्यालय या अस्पताल पहुंचने के लिए घर से निकलने वाले लोगों को रास्ते में काफी देर तक रुकना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जाम की समस्या अब कभी-कभार होने वाली परेशानी नहीं रह गई है, बल्कि नियमित हो गई है। इससे न केवल लोगों का समय बर्बाद होता है, बल्कि जरूरी कामों में भी देरी होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार, रविदास गेट और चितईपुर गेट के आसपास जाम लगने के प्रमुख कारणों में सड़क की कम चौड़ाई और पटरी पर ठेला-खोमचा लगाने से होने वाला अतिक्रमण शामिल है। सड़क किनारे ठेले और दुकानें लगने से वाहनों के गुजरने के लिए उपलब्ध जगह कम

आसपास के क्षेत्रों में जमा सिल्ट और गंदगी हटाने के लिए 15 से अधिक पंप लगाए गए हैं। इनके माध्यम से पानी के दबाव से गाद हटाने का काम कराया जा रहा है। इसके साथ ही सफाईकर्मियों और मजदूरों की मदद से सीढ़ियों तथा संपर्क मार्गों की सफाई की जा रही है। नमो घाट पर एयर शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में आयोजन से पहले घाट परिसर को साफ-सुथरा बनाने और लोगों की आवाजाही सुगम रखने की चुनौती है। नगर निगम की टीमें मशीनों और श्रमिकों की मदद से सफाई कार्य में जुटी हैं। उद्देश्य है कि आयोजन के दौरान लोगों को कीचड़, गंदगी और फिसलन के कारण परेशानी न उठानी पड़े। प्रमुख घाटों के रास्तों

पर जमा है सिल्ट गंगा का जलस्तर कम होने के बावजूद अहिल्याबाई घाट, राजघाट, राणामहल घाट, जैन घाट, अस्सी घाट, महानिवाणी घाट, मणिकर्णिका घाट और दरभंगा घाट समेत कई प्रमुख घाटों के संपर्क मार्गों पर गाद जमा है। पानी उतरने के बाद कई स्थानों पर कीचड़ और फिसलन की स्थिति बनी हुई है। इससे घाटों तक पहुंचने वाले लोगों को सावधानी से चलना पड़ रहा है। घाटों की सीढ़ियों और रास्तों पर जमा सिल्ट के कारण गंगा में स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचना भी आसान नहीं रह गया है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और उन ढ्हालुओं को अधिक परेशानी हो सकती है, जिन्हें सीढ़ियों पर उतरने-चढ़ने में दिक्कत होती है। वहीं, घाटों पर प्रतिदिन पूजा-पाठ कराने वाले

पुरोहितों और स्थानीय लोगों को भी अपने कामकाज के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काशी के घाट धार्मिक गतिविधियों के साथ पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र हैं। ऐसे में इनकी सफाई केवल सुंदरता तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुओं को स्नान और पूजा-पाठ में परेशानी घाटों पर पूजा-पाठ कराने वाले राकेश गुरु ने बताया कि गंगा का जलस्तर कम होने के बाद भी कई स्थानों पर काफी सिल्ट जमा है। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गंगा में स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचने में दिक्कत होती है और कीचड़ के कारण कई जगह चलना भी मुश्किल हो रहा है।

काशी के घाटों पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने वालों पर पुलिस की नजर, तैयार होगी लिस्ट

एजेंसी

वाराणसी। धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की नगरी काशी के घाट देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। गंगा के तट पर बसे इन घाटों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग धार्मिक अनुष्ठान, नौका विहार और पर्यटन के लिए पहुंचते हैं। वहीं, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र जैसे महाशमशान घाटों पर लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कराने आते हैं। लेकिन इन स्थानों पर मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायतें सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही काशी की छवि को लेकर भी सवाल खड़े कर रही हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस घाटों पर सक्रिय लोगों की पहचान और उनकी गतिविधियों का ब्योरा जुटाने की तैयारी कर रही है। विशेष रूप से मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार कराने आने वाले लोगों के साथ कथित बदसलूकी की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। योजना के तहत घाट पर सक्रिय नाविकों, दुकानदारों और अंतिम

संस्कार से संबंधित गतिविधियों में शामिल लोगों की सूची तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। शिकायतों और पुराने मामलों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास होगा, ताकि किसी घटना की सूचना मिलने पर जांच और नियमानुसार कार्रवाई में आसानी हो सके। मणिकर्णिका घाट पर देश के विभिन्न हिस्सों से लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कराने पहुंचते हैं। इन्हमें बड़ी संख्या ऐसे परिवारों की होती है, जो पहली बार काशी आते हैं और यहां की स्थानीय व्यवस्था से पूरी तरह परिचित नहीं होते। अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील परिस्थिति में परिजनों को पहले ही मानसिक और भावनात्मक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यदि उनके साथ अभद्र व्यवहार या विवाद की स्थिति पैदा होती है, तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मणिकर्णिका घाट पर दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतें लगभग हर चौथे

दिन पुलिस चौकी या थाने तक पहुंचती हैं। हालांकि, कई मामलों में पीड़ित पक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराने या आगे कार्रवाई कराने से बचता है। कुछ लोग विवाद से दूर रहकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं और शिकायत के आधार पर उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाने की दिशा में कदम उठाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य किसी पूरे वर्ग को संह के दायरे में लाना नहीं, बल्कि शिकायत में नाम सामने आने वाले व्यक्तियों की पहचान कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करना होना चाहिए। नाविकों और दुकानदारों का तैयार होगा रिकॉर्ड मणिकर्णिका घाट पर नाविकों, दुकानदारों और अंतिम संस्कार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों की आवाजाही रहती है। घाट पर आने वाले लोगों का इनसे अलग-अलग कामों के सिलसिले में संपर्क होता है। ऐसे में पुलिस संबंधित लोगों का व्यवस्थित ब्योरा तैयार करने

की योजना बना रही है, जिससे शिकायत मिलने पर जांच में मदद मिल सके। इस प्रक्रिया में पुराने विवादों, दर्ज मामलों और प्राप्त शिकायतों से संबंधित जानकारी भी उपयोगी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ बार-बार दुर्व्यवहार की शिकायत मिलती है, तो प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच कर तथ्यों के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति को केवल नाविक, दुकानदार या घाट पर काम करने के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। कार्रवाई के लिए शिकायत, उपलब्ध साक्ष्य और जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे। घाट पर सक्रिय लोगों की पहचान के साथ पुलिस की मौजूदगी और शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाना जरूरी है। इससे बाहर से आने वाले लोगों को यह भरोसा मिल सकता है कि किसी विवाद या दुर्व्यवहार की स्थिति में उनकी बात सुनी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरिश्चंद्र घाट पर भी बढ़ सकती है

तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 13 वर्षीय किशोर की मौत, परिवार में मचा कोहराम

एजेंसी

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में दिवियापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी गांव में रविवार शाम दुर्गा महोत्सव की कलश यात्रा में शामिल होकर पैदल चर लौट रहे 13 वर्षीय किशोर को बिहारीपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल किशोर की सैफई ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। कंचौसी गांव निवासी अहिंवरन बिहारीपुर गांव के पास पीछे से आए सिंह उर्फ लालू का 13 वर्षीय पुत्र राज रविवार शाम दुर्गा महोत्सव की कलश यात्रा में शामिल हुआ था।



कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह पैदल कंचौसी बाजार स्थित अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बिहारीपुर गांव के पास पीछे से आए सिंह उर्फ लालू का 13 वर्षीय पुत्र राज रविवार शाम दुर्गा महोत्सव की कलश यात्रा में शामिल हुआ था।

चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायल किशोर को उपचार के लिए सी शैल्या बिहारीपुर गांव के पास पीछे से आए सिंह उर्फ लालू का 13 वर्षीय पुत्र राज रविवार शाम दुर्गा महोत्सव की कलश यात्रा में शामिल हुआ था।

झाम, रविदास मंदिर गेट पर घंटों जाम में रेंगते रहे वाहन

हो जाती हैं। वहीं, सड़क पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण थोड़ी सी रुकावट भी जाम का रूप ले लेती है। लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों किनारों पर उपलब्ध जगह का व्यवस्थित इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए तो यातायात को काफी हद तक सुचारु बनाया जा सकता है। ठेला-खोमचा लगाने वालों के लिए निर्धारित स्थान तय करने और सड़क की पटरी को आवागमन के लिए खाली रखने की जरूरत है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि जब तक सड़क की चौड़ाई और अतिक्रमण जैसी मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक केवल वाहनों को नियंत्रित करने से जाम से स्थायी राहत मिलना मुश्किल है। पुलिस की मौजूदगी के बाद भी नहीं सुधर रही स्थिति स्थानीय नागरिक राजेश ने बताया कि रविदास गेट और चितईपुर गेट के आसपास



आए दिन जाम लगता है। सुबह और शाम के समय स्थिति अधिक खराब हो जाती है। कई बार वाहनों की कतार दो किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसमें स्कूली बच्चों से लेकर मरीजों तक को परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मों मौके पर मौजूद रहते हैं और वाहनों को निकालने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद जाम की समस्या

लगातार बनी हुई है। उनके मुताबिक, पुलिस की कोशिशों के बाद भी सड़क पर वाहनों का दबाव और सीमित जगह होने के कारण यातायात सामान्य जाम में सने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की ओर से तत्काल यातायात नियंत्रित करने के प्रयास जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ सड़क पर अतिक्रमण रोकने और उपलब्ध जगह का बेहतर प्रबंधन करने की भी आवश्यकता है।

भारत के सबसे बड़े आईपीओ का ऐलान, जियो प्लेटफॉर्म्स ने तय किया प्राइस बैंड

1,065-1,119 रुपए प्रति शेयर पर जारी होगी इक्विटी, 21 अक्टूबर से लगभग दाय

नई दिल्ली ।

जियो प्लेटफॉर्म्स के बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) के लिए प्राइस बैंड की घोषणा कर दी गई है। कंपनी ने अपने शेयरों की कीमत 1,065 से 1,119 रुपए प्रति शेयर तय की है, जिससे यह आईपीओ भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम बनने जा रहा है। इस मेगा आईपीओ के जरिए जियो प्लेटफॉर्म्स 30,200 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इस ऑफर के साथ कंपनी का कुल इक्विटी मूल्यांकन 9.8-10.3 लाख करोड़ रुपए (लगभग 101-107 बिलियन डॉलर) तक पहुंच जाएगा। यह आईपीओ पूरी तरह से एक फ्रेश इश्यू होगा, जिसका अर्थ है कि शेयरों की बिक्री से जुटाई गई पूरी रकम सीधे कंपनी के बैंक खाते में जाएगी। इस फंड का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के मौजूदा कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। शेष राशि का उपयोग 5जी नेटवर्क के विस्तार, अत्याधुनिक डेटा सेंटरों के निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टेक्नोलॉजी के विकास जैसी भविष्य की परियोजनाओं में निवेश के लिए किया जाएगा। निवेशकों के लिए इस ऐतिहासिक आईपीओ में दांव लगाने का अवसर 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रहेगा। वहीं शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने की संभावना है। दिवाली से ठीक पहले लिस्टिंग की टाइमलाइन से बाजार में सकारात्मक त्योहारी सेंटिमेंट्स और बेहतर नकदी प्रवाह का फायदा मिलने की उम्मीद है। 30,200 करोड़ रुपए का यह आईपीओ, हुंडई मोटर इंडिया के 27,858.75 करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर देश का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर बन गया है।

एसआईपी से पूरा करें अपनी ड्रीम एसयूवी का सपना! 5 साल में जमा करें 20 लाख

मुंबई ।

एसयूवी खरीदने का सपना देखते हैं, लेकिन एक साथ बड़ी रकम खर्च करना मुश्किल लगता है। म्युचुअल फंड की सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) ऐसे में मददगार साबित हो सकती है। अगले पांच साल में अपनी पसंदीदा एसयूवी घर लाने के लिए आप अभी से मासिक निवेश शुरू करके 20 लाख रुपये तक जुटाने की योजना बना सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पांच साल बाद 20 लाख रुपये की एसयूवी खरीदने के लिए 10 फीसदी सालाना रिटर्न मानकर, आपको हर महीने लगभग 26,000 रुपये की एसआईपी करनी होगी। इसमें 15.6 लाख रुपये का निवेश और 4.4 लाख रुपये का अनुमानित रिटर्न शामिल है। वहीं 15 लाख रुपये के लक्ष्य के लिए प्रतिमाह 19,500 रुपये निवेश की आवश्यकता होगी। हालांकि, वित्तीय योजनाकार चेतावते हैं कि शेयर बाजार के लिए पांच साल लंबा समय नहीं है, और इक्विटी म्युचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती। ऐसे में केवल 10 फीसदी रिटर्न के भरोसे योजना बनाना जोखिम भरा हो सकता है। निवेश से पहले भविष्य में कार की कीमत, संभावित रिटर्न, लोन ब्याज और ईएमआई के बोझ पर गंभीरता से विचार करें, ताकि आपके अन्य वित्तीय लक्ष्य प्रभावित न हों।

आईएमएफने भारत का ग्रोथ अनुमान 6.4 से बढ़ाकर 7 फीसदी किया - वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की मजबूत स्थिति नई दिल्ली ।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की आर्थिक क्षमता पर अपना गहरा विश्वास व्यक्त करते हुए वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 7 फीसदी कर दिया है। पहले यह अनुमान वित्त वर्ष 27 के लिए 6.4 फीसदी और वित्त वर्ष 28 के लिए 6.7 फीसदी था। यह बढ़ोतरी भारतीय केंद्रीय बैंक आरबीआई और विश्व बैंक द्वारा भी अपने वृद्धि अनुमानों को बढ़ाने के बाद आई है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को रेखांकित करती है। आईएमएफ के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत गति से आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 27 और 28 दोनों के लिए वृद्धि दर का अनुमान 7 फीसदी पर स्थिर किया गया है। यह सकारात्मक बदलाव देश की दमदार आर्थिक रफ्तार, मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन के कारण संभव हुआ है। आईएमएफ ने भारत की अनुकूल आबादी संरचना, एक बड़े और बढ़ते घरेलू बाजार तथा लगातार जारी संरचनात्मक सुधारों को भविष्य की सतत ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण कारक बताया है। यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। आईएमएफ को 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था 3.1 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है, जो भारत के अनुमान से काफी कम है।

जोसेफिन की कप्तानी में भारत का दौरा करेगी जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीम

हारे (एंसीसी) जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीम अनुभवी ऑलराउंडर जोसेफिन नकोमो की कप्तानी में भारत दौर पर पहुंचेगी। 15 सदस्यीय जिम्बाब्वे की टीम 16 अक्टूबर से भरत दौर पर रहेगी। ये उसकी महिला टीम का पहला भारत दौरा होगा। यह दौरा जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट के लिए एक अहम मौल का पथर साबित होगा। इससे वह वे विश्व की शीर्ष टीमों में से एक भारत के खिलाफ खेलकर अपनी क्षमताओं का आंकलन कर सकेगी। करेंगी। जोसेफिन अपनी ऑलराउंड क्षमता और नेतृत्व कौशल के लिए जानी जाती हैं के ऊपर अपनी टीम को इस चुनौतीपूर्ण अभियान में मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी होगी।

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इस दौर के लिए अपनी टीम में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में शामिल रही मुख्य खिलाड़ियों को ही बनाये रखा है। बकरार जिससे की टीम में निरंतरता बनी रहे। जिम्बाब्वे ने हारे में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गप्

दूसरे एकदिवसीय में चार विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाली युवा तेज गेंदबाज न्याशा ग्वांजुरा और मिशेल मावुंगा को भी भारतीय दौर के लिए रखा गया है। 15 सदस्यीय टीम में शामिल इन दोनों गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मिलकर सात विकेट लेकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था, और उनसे भारतीय पिचों पर भी अपनी स्विंग और गति से प्रभावित करने की उम्मीद होगी। उनका प्रदर्शन इस दौर पर जिम्बाब्वे के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

इस दौर की शुरुआत तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ होगी, जो 16, 18 और 20 अक्टूबर को छठीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेले जाएंगे। इसके बाद, टीम गुजरात के बड़ौदा का रुख करेगी, जहाँ 23, 25 और 28 अक्टूबर को तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय (वनडे) मैच निर्धारित हैं। यह कार्यक्रम खिलाड़ियों को दोनों प्रारूपों में खुद को



आईटी सर्च में नाम आने पर रकुल प्रीत सिंह ने दी सफाई

अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने इनकम टैक्स छापां से अपना नाम जुड़ने की खबरों पर रिएक्ट किया। अभिनेत्री ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। दरअसल, 28 सितंबर को आयकर विभाग ने अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और फिल्म निर्माता वासु भगनानी से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। 28 सितंबर 2026 को मुंबई में आयकर विभाग ने रकुलप्रीत सिंह, वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज के परिसरों की तलाशी ली थी। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मीडिया द्वारा गलत अफवाहों को फैलाने पर अफसोस जताया। उन्होंने लिखा, ‘यह देखकर बहुत दुख होता है कि आजकल कुछ खुद की रिपोर्टर कहने वाले लोग और कुछ बड़े मीडिया पत्रकार बिना सच्चाई जाने खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं। इसलिए, मैं एक बार फिर सब कुछ साफ कर देती हूँ।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘अभी हाल ही में हमारे घर में जो तलाशी हुई है, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। इस बात हर कोई वाकिफ है कि मैं एक फौजी परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। मैं अपनी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंची हूँ और 20 साल की उम्र से एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना पूरा टैक्स भी भरती आ रही हूँ।’ अभिनेत्री ने साफ किया कि उनका नाम किसी भी गैरकानूनी कामों से जुड़ा नहीं है। उन्होंने लिखा, ‘मैं किसी भी तरह के गैरकानूनी विदेशी लेनदेन में शामिल नहीं हूँ, न तो खुद के लिए और न ही किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए। मैं यह भी साफ कर दूँ कि मेरे नाम पर देश या विदेश में कहीं भी गैरकानूनी प्रॉपर्टी नहीं है। न ही कभी किसी ने मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट की और न ही मैं इस तरह से तोहफे स्वीकार करती हूँ।’ अभिनेत्री ने अफवाह फैलाने वाले मीडिया संस्थानों से अपील करती हैं, कि वे इस तरह की खबरें न फैलाएं। उन्होंने लिखा, ‘जिन्होंने मेरे खिलाफ मनगढ़ंत खबरें छपी हैं। मैं उनसे उस खबर को वापस लेने की अपील करती हूँ, साथ ही सच्चाई बताने के लिए कहती हूँ। मैं समझती हूँ कि मीडिया पर भी अपना बिजनेस चलाने का दबाव होता है लेकिन यह दबाव सच्चाई की कीमत पर नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी किसी की इज्जत और रोजी-रोटी की कीमत पर तो नहीं होना चाहिए।’



शाहरुख की फिल्म में करीना की भी हुई एंट्री

अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। मगर इस फिल्म का गाना ‘डैडी कूल’ और भी ज्यादा खास होने वाला है। खबर है कि इस गाने में बादशाह के साथ करीना कपूर भी दिखाई देगी।

‘डैडी कूल’ में क्या है खास

शाहरुख खान और करीना कपूर खान आगामी एक्शन फिल्म ‘किंग’ के एक महत्वपूर्ण गाने में एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार करीना ने ‘डैडी कूल’ नामक इस गाने में विशेष भूमिका निभाने के लिए हामी भरी है, जिसकी शूटिंग इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में एक भव्य तरीके से होगी।



पहले भी साथ काम कर चुके शाहरुख-करीना

फिल्म ‘किंग’ का गाना डैडी कूल ऐसा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, जिसके लिए शाहरुख और करीना साथ काम कर रहे हों। इससे पहले करीना और शाहरुख ‘अशोका’, ‘कभी खुशी कभी गम’ और ‘रा.वन’ जैसी बड़ी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा करीना शाहरुख की कई फिल्मों में कैमियो या स्पेशल गाना भी कर चुकी हैं। कविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘डैडी कूल’ को इस एक्शन फिल्म के मुख्य गानों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। प्रोडक्शन शेड्यूल के अनुसार, करीना को दक्षिण अफ्रीका में शाहरुख के साथ अपने हिस्से की शूटिंग के लिए लगभग पांच दिन दिए गए हैं। क्रॉस-कल्चरल देखने को मिलेगा रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दो बॉलीवुड सितारों को एक साथ लाने के अलावा, इस सीक्वेंस में एक बड़ा क्रॉस-कल्चरल सहयोग भी देखने को मिलेगा। इस गाने में एक भारतीय कलाकार एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार के साथ नजर आएंगे।

हनुमान अंश की सफलता पर ऋचा चड्ढा ने तोड़ी चुप्पी

‘हनुमान अंश’ को सिनेमाघरों में दो महीने होने वाले हैं। यह फिल्म भारत में 300 करोड़ से ज्यादा और वर्ल्डवाइड 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। अब इसकी सफलता पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपनी राय दी है। बॉलीवुड की बेबाक और संजीदा अभिनेत्री ऋचा चड्ढा का मानना है साल 2026 को कटेंट आधारित सिनेमा के लिए बड़ा साल कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दर्शकों की पसंद में कोई बड़ा बदलाव आया है।

‘हनुमान अंश’ की सफलता पर ऋचा का बेबाक विश्लेषण

2026 को ‘कटेंट-ड्रिवन सिनेमा’ का लैंडमार्क साल कहे जाने पर असहमति जताते हुए ऋचा चड्ढा ने कहा, अगर बात सिर्फ ‘हनुमान अंश’ के संदर्भ में है, तो वह एक अलग मामला है। इसके अलावा इस साल और क्या चला है? हमारी तुलना हॉलीवुड से नहीं की जा सकती। पौराणिक और धार्मिक फिल्में भारतीय दर्शकों के बीच हमेशा से सुरक्षित और लोकप्रिय रही हैं। ये फिल्में तो लोग देखते ही हैं। इसलिए यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि इंडस्ट्री में अचानक कुछ बहुत बेहतरीन होने लगा है। ऋचा का मानना है कि



विदेशी निवेशकों ने 2026 में भारतीय शेयर बाजार से निकाले 3 लाख - भारतीय कंपनियों का उच्च मूल्यांकन भी बढ़ा रहा है निवेशकों की चिंता



नई दिल्ली ।

भारतीय शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ऐतिहासिक निकासी का दौर जारी है, जिसके चलते बाजार पर दबाव बढ़ गया है। कैलेंडर वर्ष 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 3.08 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निकाली है, जो पिछले वर्ष (2025) की कुल निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपए से लगभग दोगुनी है। यह लगातार बिकवाली भारतीय बाजार की मौजूदा चुनौतियों को उजागर करती है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार, 12 अक्टूबर तक एफपीआई ने द्वितीयक बाजार से 3.64 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है। हालांकि, नई

धार्मिक या पौराणिक विषयों पर बनी फिल्मों का एक स्थापित दर्शक वर्ग है, जो बिना किसी झिझक के थिएटर तक आता है। इसे पुरे सिनेमा उद्योग में आए वैचारिक या रचनात्मक बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

राइटर्स को मिले बेहतर पैसे, तभी बदलेगा सिनेमा

भारतीय फिल्म उद्योग को वास्तव में कटेंट-संचालित बनाने के उपाय पर बात करते हुए ऋचा ने सबसे अहम मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि जब तक पटकथा लेखकों को सही सम्मान और बेहतर पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, तब तक बड़े बदलाव की उम्मीद करना बेमानी है। ‘हनुमान अंश’ का 2 करोड़ के बजट से 423 करोड़ तक का ऐतिहासिक सफर विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। बेहद शांत शुरुआत करने वाली इस फिल्म को ‘वर्ड ऑफ माउथ’ का ऐसा जबरदस्त सहारा मिला कि यह 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट बन गई।

भारतीय इस्पात नीति विजन 2047, आयात निगरानी के लिए एआई का उपयोग

असामान्य रुझानों का पता लगाने और घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर

नई दिल्ली ।

भारत सरकार ने अपनी प्रस्तावित नेशनल स्टील पॉलिसी विजन 2047 के मसौदे में इस्पात आयात के असामान्य रुझानों का समय रहते पता लगाने और घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित व्यवस्था और उन्नत डेटा विश्लेषण के उपयोग का प्रस्ताव किया है।

नीति का उद्देश्य 2047 तक भारतीय इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करना है। यह अनावश्यक आयात निर्भरता कम करने, इस्पात क्षेत्र को मजबूत बनाने और प्रतिस्पर्धात्मकता व दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष व्यापार, घरेलू क्षमता और गुणवत्ता पर आधारित तीन-स्तरीय रणनीति अपनाएगी।

मौजूदा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 की समीक्षा के बाद यह नई नीति एआई और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्राथमिकताओं पर

अधिक ध्यान केंद्रित करती है। मसौदे में देश की इस्पात उत्पादन क्षमता को 60.4 करोड़ टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह विशेष रूप से घटिया या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले इस्पात के आयात पर रोक लगाने पर जोर देती है, जिसे घरेलू उत्पादकों के लिए बड़ी चुनौती बताया गया है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए जांच, प्रमाणन और वास्तविक समय में आयात की निगरानी के साथ-साथ असामान्य रुझानों का जल्द पता लगाने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाएगा।

मसौदे में कहा गया है कि एआई आधारित आयात निगरानी और अन्य व्यापार सुधारात्मक उपायों सहित घटिया और कम गुणवत्ता वाले इस्पात के आयात को हतोत्साहित करने के उपाय जारी रहेंगे। जहां अनुचित व्यापार गतिविधियां साबित हों, वहां समय पर डॉपिंग-रोधी और सुस्त्रा उपाय किए जाएंगे।

उबरन । ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उरबन में जारी टैस्ट मैच के दौरान हेल्मेट पर पर गेंद लगने के बाद से ही कनकशन जांच चल रही है। रियर में चोट लगने पर ये जांच होती है जिससे खिलाड़ी एक तय समय तक मैदान से दूर रहता है। स्मिथ के हेल्मेट पर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्त्ज की एक तेज बाउंसर लग गयी थी। जिससे वह कनकशन जांच के दायरे में आये। अब उनके बाहर होने से ऑस्ट्रेलियाई टीम की मुश्किलें बढ़ गयी हैं।

उत्तर और दक्षिण कोरिया में बढ़ा तनाव: किम जोंग उन ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें

सिओल , एजेंसी। उत्तर कोरिया ने सोमवार को अपने पूर्वी समुद्री इलाके की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। यह जानकारी दक्षिण कोरिया की सेना ने दिया। यह हाल के दिनों में हथियारों के प्रदर्शन का एक और मामला है, जिससे कूटनीतिक बातचीत लंबे समय से रुकी होने के बीच तनाव और बढ़ गया है।

जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने क्या बताया? – दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आस-पास के इलाके से दागी गईं। हाल के वर्षों में देश ने अपने हवाई अड्डे का इस्तेमाल एक मुख्य लॉन्च साइट के तौर पर किया है। जॉइंट चीफ्स ने तुरंत यह नहीं बताया कि कितनी

मिसाइलें देखी गई या वे कितनी दूर तक गईं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने कम से कम दो मिसाइलें देखीं और अनुमान लगाया कि ये हथियार देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर समुद्र में गिरे।

दक्षिण कोरिया ने किया हथियार के उड़ान परीक्षण- यह लॉन्च दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को अपने पहले घरेलू स्तर पर विकसित हाइपरसोनिक हथियार के उड़ान परीक्षण के कुछ दिनों बाद किया। इस हथियार को ध्वनि की गति से कम से कम पांच गुना तेज उड़ने और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रपति ली जे-यूंग ने इसे दक्षिण कोरिया की पारंपरिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।



उत्तर कोरिया क्यों कर रहा इतने परीक्षण?– सियोल के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए, उत्तर कोरिया अपने परमाणु-सक्षम हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के लिए लगातार हथियारों का परीक्षण कर रहा है। इसमें 3 अक्टूबर को किया गया वह परीक्षण भी शामिल है, जिसे उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट-रेंज मिसाइल बताया था। इसे दक्षिण कोरिया और जापान की मिसाइल सुरक्षा प्रणालियों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है।

उत्तर कोरिया ने मिसाइल के और भी टेस्ट किए हैं, लाइव-फायर ड्रिल की हैं और एक नया युद्धपोत भी शामिल किया है। नेता किम जोंग-उन अपने परमाणु

हथियार कार्यक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लंबे समय से रुके हुए कूटनीतिक बातचीत को फिर से शुरू करने के प्रस्तावों को भी ठुकरा रहे हैं।

दक्षिण कोरिया के तीन सैनिक कैसे घायल हुए? – पिछले महीने भारी हथियारों से लैस अंतर-कोरियाई सीमा के पास लैंड माइन धमाकों में दक्षिण कोरिया के तीन सैनिकों के घायल होने के बाद तनाव और बढ़ गया। दक्षिण कोरिया की सेना और अमेरिका के नेतृत्व वाली यूनाइटेड नेशंस कमांड ने निष्कर्ष निकाला कि ये धमाके उत्तर कोरिया की ओर से लगाए गए उपकरणों के कारण हुए थे। हालांकि, उत्तर कोरिया ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है

और माफी की दक्षिण कोरिया की मांग का मजाक उड़ाया है।

हाल के वर्षों में, वॉशिंगटन के साथ परमाणु बातचीत में लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बीच, किम ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी तरह की कूटनीति और सहयोग रोक दिया है और पड़ोसी देश को अपना पक्का दुश्मन बताया है। उन्होंने अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत फिर से शुरू करने की अपील को ठुकरा दिया है। 2019 में यह बातचीत टूट गई थी। उनकी सरकार की मांग है कि वॉशिंगटन प्योंगयांग के प्रति अपनी दुश्मनी वाली नीति छोड़े और बातचीत के लिए शर्त के तौर पर उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार खत्म करने की मांग को हटाए।

संक्षिप्त समाचार

भावनाओं को समझने में महिलाएं आगे, पर यही खूबी बन जाती है उनके लिए बड़ा बोझ

ज्यूरिख, एजेंसी। किसी बैठक में सहकर्मी का अचानक चुप हो जाना, किसी दोस्त के चेहरे से उसकी परेशानी भांप लेना या तनाव के बीच सही बात कहकर माहौल संभाल लेना। ये ऐसे कौशल हैं, जो रिश्तों को बेहतर बनाने के साथ कामकाज को भी आसान करते हैं।

लेकिन जब इन्हें किसी की स्वाभाविक खूबी मान लिया जाता है, तो यही क्षमता उसके लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी बन सकती है। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा ही होता है।

लिमरिक विश्वविद्यालय की मैरी एम ह्युसफेल्ड और ज्यूरिख विश्वविद्यालय के योखेन मेंगेस ने 1995 से 2023 तक प्रकाशित शोधों की समीक्षा की। इसमें 76 देशों के छह लाख से अधिक लोग शामिल थे।



अध्ययन में औसतन महिलाओं का भावनात्मक बुद्धिमत्ता में प्रदर्शन पुरुषों से बेहतर पाया गया। यह बहुत खास तौर पर दूसरों की भावनाओं को पहचानने, उनके कारण समझने और उनसे निपटने में मदद करने के मामले में दिखी। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं कि हर महिला इस मामले में हर पुरुष से बेहतर होती है।

बचपन से मिलता है ज्यादा अभ्यास- भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और सभालने की क्षमता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इसकी एक वजह बचपन में लड़के-लड़कियों की परवरिश का अंतर हो सकता है। माता-पिता अक्सर बेटियों को भावनाओं पर बात करने और उन्हें शब्दों में व्यक्त करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, जबकि बेटों को कई बार भावनाएं दबाने की सीख मिलती है।

इस तरह लड़कियों को दूसरों की भावनाएं समझने और उनके अनुरूप प्रतिक्रिया देने का अधिक अभ्यास मिलता है। जैसे कोई भाषा या वाद्य यंत्र सीखने से उसमें दक्षता बढ़ती है, वैसे ही भावनात्मक कौशल भी अभ्यास से निखरते हैं। वर्ष 2019 में 58 अध्ययनों के मेटा-विश्लेषण में भी पाया गया कि प्रशिक्षण से भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है। समस्या तब शुरू होती है, जब महिलाओं की इस क्षमता को कौशल मानने के बजाय उनकी स्वाभाविक जिम्मेदारी समझ लिया जाता है। दम्पतर में टीम का तनाव संभालना, परेशान सहकर्मी को सहारा देना और विवाद शांत करना अक्सर उन्हीं के हिस्से आता है। इससे कामकाज सुचारु रहता है, लेकिन प्रदर्शन के अकालन और पुरस्कारों में इस योगदान को जगह नहीं मिलती।

अमेरिका-ब्रिटेन में पढ़ा रहे पाकिस्तानी शिक्षाविदों ने उठाई आवाज, इमान मजारी और उनके पति को रिहा करे पाकिस्तान

लंदन, एजेंसी। पाकिस्तान में वकील इमान जैनब मजारी-हॉजिर और हदी अली चड्ढा की हिरासत को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में कार्यरत पाकिस्तानी मूल के शिक्षाविदों ने आवाज उठाई है। उन्होंने दोनों वकीलों के खिलाफ आरोप वापस लेने और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है। शिक्षाविदों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के शासन से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। लाहौर में जारी संयुक्त बयान में शिक्षाविदों ने पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन की स्थिति पर चिंता जताई। यह बयान जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के आकिल शाह की पहल पर जारी किया गया। बयान के मुताबिक, जनवरी 2026 में इमान मजारी और हदी चड्ढा को सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून (पैरेसीए) के तहत 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इन पोस्ट में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की



आलोचना की गई थी। शिक्षाविदों के अनुसार, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2026 को दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने एक अन्य मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया। संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों अब भी हिरासत में हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि इमान मजारी जबरन गुमशुदगी के मामलों पर आवाज उठाती रही हैं और पीड़ितों तथा उनके

परिवारों का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर संस्थाओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना भी की है। वहीं, हदी चड्ढा ने ईशान्दिा के आरोपों का सामना कर रहे लोगों और मृत्युदंड का फैसला कैदियों का बचाव किया है। बयान में कहा गया कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल असहमति की आवाज दबाने या वकीलों को उनकी पैरवी के कारण डराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

पीयूष गोयल की राहुल गांधी को सीधी चुनौती: वोट चोरी के सबूत पेश करें पूरा विपक्ष

-राहुल गांधी आरोप लगाकर भाग जाने वाले नेता

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने राहुल गांधी के रुख को पूरी तरह से दोहरा मानदंड और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने राहुल पर शूट एंड स्कूट (आरोप लगाकर भाग जाने) की राजनीति करने का आरोप लगाकर सीधी चुनौती दी कि वे इन गंभीर आरोपों पर केवल विरोध-प्रदर्शन करने के बजाय कानूनी तरीकों से चुनाव आयोग के सामने सबूत पेश करें। केंद्रीय मंत्री गोयल ने सवाल किया कि अगर उनके पास अपने दावों के समर्थन में ठोस प्रमाण हैं, तब उन्होंने अब तक चुनाव आयोग को कोई हलफनामा क्यों नहीं सोपा है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने राहुल गांधी से 10 तीखे सवाल पूछकर कांग्रेस के शासनकाल का ऐतिहासिक ब्योरा देकर आरोप लगाया कि देश में चुनाव आयोग की साख को सबसे



ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने ही पहुंचाया है। उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के दौरान, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगने के बावजूद, कांग्रेस ने उन्हें पदोन्नत कर मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को ताक पर रखकर कई पूर्ण चुनाव आयुक्तों को राजनीतिक पुरस्कार बांटे। इसमें से एक को संसद का टिकट दिया गया, एक

केंद्रीय मंत्री बनाना, आयोग की स्वायत्तता पर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रहारों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके विपरीत, पीयूष गोयल ने दावा किया कि मौजूदा एनडीए सरकार ने चुनाव आयोग को पूर्ण संवैधानिक स्वायत्तता प्रदान की है और उसकी निष्पक्षता में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर तोखा प्रहार कर गोयल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस इस प्रक्रिया को गलत मानती थी, बिहार और बंगाल चुनावों के दौरान इस पर आपत्ति क्यों नहीं जाहिर की। केंद्रीय मंत्री गोयल ने निष्कर्ष निकालकर कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर बार-बार निराधार सवाल उठाना भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की एक सोची-समझी साजिश है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा।

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दिया इस्तीफा

-पार्टी पर हिंदुत्व और बालासाहेब की विचारधारा से भटकने का आरोप



मुंबई , एजेंसी। महाराष्ट्र में उड़ब ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रमुख उत्तर भारतीय चेहरे और विधायक आदित्य ठाकरे के करीबी राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे पार्टी के अपनी मूल हिंदुत्व विचारधारा से दूर जाने और कांग्रेस के साथ बढ़ती राजनीतिक नजदीकियों को मुख्य वजह बताया है। पार्टी छोड़ने के बाद आनंद दुबे ने कहा कि स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना का गठन कट्टर हिंदुत्व, मराठी अस्मिता और मजबूत राष्ट्रवाद के आधार पर हुआ था। हालांकि, मौजूदा समय में शिवसेना (यूबीटी) की राजनीतिक दिशा और उनकी व्यक्तिगत वैचारिक प्रतिबद्धताओं के बीच गहरा मतभेद पैदा हो गया है, जिससे पार्टी का पक्ष रखना असंभव हो गया था।

अल नीनो के प्रभाव के बीच दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून की दस्तक

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा नया मौसमी सिस्टम

नई दिल्ली, एजेंसी। देश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के साथ ही मौसमी चक्र में बदलाव का दौर शुरू हुआ है। बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) विकसित होने और उत्तर-पूर्वी मानसून के आगमन से दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इस नए मौसमी तंत्र के प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है। हालांकि, त्योंहारी सीजन के दौरान देश भर में व्यापक और भारी बारिश की अफवाहों को खारिज कर आईएमडी ने साफ किया है कि अक्टूबर में औसत वर्षा सामान्य या उससे कम रहने का ही अनुमान है। उत्तर-पूर्वी मानसून, जो कि शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है, मुख्य रूप से देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को प्रभावित करता



है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने वाली वर्षा दक्षिण भारत की कृषि, जलाशय भराव और जलापूर्ति के दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जाती है। दूसरी तरफ, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अल नीनो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को प्रभावित करता

है और आमतौर पर भारत में मानसून की वर्षा को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। हालांकि, इसका असर स्थानीय समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आईएमडी ने त्योंहारी सीजन में यात्रा करने वालों और सार्वजनिक आयोजनों के आयोजकों को सलाह दी है कि वे भ्रामक जानकारीयों से

बचें और अपने स्थानीय जिला स्तर के मौसम पूर्वानुमानों पर नजर रखें। दशहरे से लेकर दीपावली के बीच अलग-अलग राज्यों में मौसम का मिजाज भिन्न हो सकता है, जहां कुछ तटीय इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है, वहीं देश के अधिकांश अंदरूनी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है।

अमेरिका में राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी, मिडटर्म चुनाव में क्यों बदला भारतीय-अमेरिकियों का प्लान?

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत और प्रवासी भारतीयों के खिलाफ नीतियों ने राजनीतिक दमखम रखने वाले भारतीय प्रवासियों को नए सिरे से अमेरिकी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के पुरजोर प्रयासों के लिए प्रेरित किया है। इसलिए अब भारतीय-अमेरिकी केवल सांसद बनकर अमेरिकी सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव में अपने मुद्दों के प्रति सहानुभूति रखने वाले अन्य उम्मीदवारों का भी समर्थन कर रहे हैं।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेताओं ने कहा कि कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों में मजबूत मौजूदगी के बावजूद समुदाय के पीछे की प्रतियर्था के कारण निर्वाचितता पर जोर



पर भारतीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व कम रहा है। प्रवासी समुदाय के एक नेता ने कहा,ऐसे मौके आए हैं जब कई भारतीय-अमेरिकी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। इससे समुदाय के उम्मीदवारों की कम संख्या में जीत हुई।

उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए एकजुटता पर जोर

दिया। कार्यकाल पूरा कर रही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारतीय मूल के छह सदस्य हैं, लेकिन यह संख्या घटकर चार रह सकती है। इलिनोइस से राजा कृष्णमूर्ति और मिशिगन से श्री थानेदार प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके।

भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना (कैलिफोर्निया-17), प्रमिला जयपाल

(वाशिंगटन-7), एमी बेरा (कैलिफोर्निया-3) और सुहास सुब्रमण्यम (वर्जीनिया-10) फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के चुनाव में मैदान में हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होने वाले मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्यों और ऊपरी सदन सीनेट के 100 सदस्यों में से करीब एक-तिहाई का चुनाव होता है। इन चुनावों में कई राज्यों के गवर्नर व विधानसभाओं के साथ कुछ शहरों के मेयर और अन्य स्थानीय अधिकारियों के चुनाव भी शामिल होते हैं। नतीजे तय करते हैं कि कांग्रेस पर किस दल का नियंत्रण होगा और राष्ट्रपति की विधेयक पारित कराने की क्षमता पर भी उनका असर पड़ सकता है।